●वर्ष-5
●अंक-243
रायपुर, गुरुवार
28 मई 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

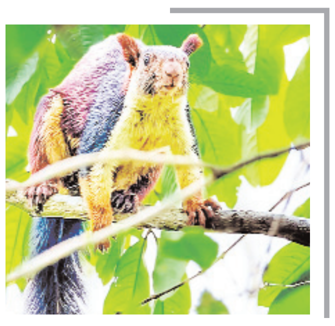

पेज-8› बारनवापारा के देवपुर जंगल में...

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी

- डीलरों का बढ़ेगा कमीशन और राज्यों को मिलेगी आर्थिक सहायता
- 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की तैयारी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बधुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार राशन वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनसे राज्यों, राशन डीलरों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

राज्यों को आर्थिक सहायता

कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला राज्यों को आर्थिक सहायता देने से जुड़ा है। मंत्री ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बड़े गोदामों से अनाज को जिलों, ब्लॉकों और अंततः राशन दुकानों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब केंद्र सरकार इस परिवहन और वितरण व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी, जिससे राशन आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुचारु हो सकेगी।

राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन

कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ाने का है। लंबे समय से राशन दुकानदार अपने कमीशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे देशभर के लाखों राशन डीलरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

लाभार्थियों का पंजीकरण

कैबिनेट का तीसरा और सबसे अहम फैसला जो राशन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का है। सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों की मदद से लाभार्थियों का पंजीकरण करेगी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सही व्यक्ति तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल और तकनीक आधारित व्यवस्था से पूरे पीडीएस नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

भीषण गर्मी पर हुई चर्चा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान देश में जारी भीषण लू की स्थिति पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पूरे राष्ट्र की भावना के साथ काम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य, जल संसाधन और अन्य विभागों द्वारा नागरिकों को राहत और सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर विशेष चर्चा की गई।

गरीबों पर पहुंचेगा पूरा लाभः अमित शाह

एआई-इनेबल्ड लाभार्थी रजिस्ट्री निर्माण, जीपीएस ट्रैकिंग और क्यूआर कोड टैगिंग जैसे हाईटेक सिस्टम के माध्यम से गरीबों तक सस्ते अनाज और अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाया जाएगा. साथ ही राज्यों के बढ़ते लॉजिस्टिक कॉस्ट को आर्थिक समर्थन प्रदान करने तथा राशन दुकानों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान किया गया है.मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य के भीतर खाद्यान्नों के परिवहन एवं प्रबंधन और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के वितरकों के मार्जिन के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता के मानकों में संशोधन को भी मंजूरी दी। सार्थक-पीडीएस योजना में दो मौजूदा योजनाओं- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन और एफपीएस वितरक मार्जिन के लिए सहायता तथा 'स्मार्ट पीडीएस' को समाहितकिया गया है।

45 डिग्री का टॉर्चर साथ में लू के थपेड़े...

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने का किया आह्वान

नईदिल्ली। नयी दिल्ली, 27 मई (वार्ता) देश में गर्मी की विकरालता चरम पर है और कहर बरपा रही लू के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने और सभी मंत्रालयों से जनता को गर्मी तथा लू से बचाने के लिए हर संभव उपाय करने का आह्वान किया है।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं।

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र देश के सबसे अधिक गर्म इलाकों में बना हुआ है। ब्रह्मपुरी में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस और नागपुर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के वर्धा, अमरावती और चंद्रपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो दिनों तक गंभीर हीटवेव की चेतावनी दी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कई हिस्सों में भी लू से गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम राजस्थान और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। तेलंगाना के 10 जिलों में भी हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

इस बीच प्रधानमंत्री ने देश में प्रचंड गर्मी और लू के दौर को देखते हुए देशवासियों से सावधानी बरतने और सभी मंत्रालयों से जनता को गर्मी और लू से बचाने के लिए हर संभव उपय करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से लू और गर्मी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से पशु-पक्षियों के लिए भी घरों , दफ्तरों और दुकानों के बाहर बर्तन में पानी रखने की अपील की तथा लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने और अत्यधिक गर्मी की स्थिति में दूसरों को पानी देकर उनकी मदद करने का सुझाव दिया है।

पिछले एक पखवाड़े से प्रचंड गर्मी और लू का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं लू तो कहीं तेज आंधी, गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से लेकर भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है , वहीं कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जतायी है। किसानों को फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को समय-समय पर मौसम अपडेट और बिजली गिरने की चेतावनी के लिए मौसम , मेघदूत और दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह भी दी गयी है।छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है तथा कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है तथा अगले तीन दिनों तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की वजह से राज्य के खैरागढ़ जिले के दल्लीखोली-लछना जंगल में मोर, मोरनी, एशियन पाम सिवेट समेत 15 से 20 वन्यजीव और पक्षी मृत पाए गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से भारतीय वन सेवा के लिए चयनित रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव निवासी श्री अजय गुप्ता ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अजय को भारतीय वन सेवा में चयनित होने पर बधाई देते हुए इसे पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर वनांचल क्षेत्र के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण बताया।

प्रदेश में लागू होगी 'इम्प्रूड राईस स्कीम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन 'इम्प्रूड राईस स्कीम' को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में आज न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने की। इसमें छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेशभर के राईस मिलर्स ने भाग लिया।

कार्यशाला में खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि भारत सरकार आगामी खरीफ वर्ष में 'इम्प्रूड राईस स्कीम' को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राईस मिलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे।कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कान्ति लाल बोथरा, महामंत्री विष्णु बिंदल, कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं मिलर्स उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला आयोजन के लिए खाद्य विभाग का आभार व्यक्त करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यशाला में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली 'इम्प्रूव्ड राईस स्कीम' के विभिन्न प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, अनुबंध प्रक्रिया, लागत एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 10 प्रतिशत अरवा ब्रोकन चावल एवं 5 प्रतिशत उसना ब्रोकन चावल के निर्धारित मानकों की जानकारी दी।

प्रमुख समाचार

सिद्धारमैया के इस्तीफे का सस्पेंस आज होगा खत्म

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व के भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, राज्य मंत्री जी परमेश्वर ने एक बड़ा अपडेट साझा करते हुए कहा कि 28 मई, गुरुवार तक भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में सत्ता संघर्ष की चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पद छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का नाम अभी स्पष्ट नहीं है।

मंगलवार को सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के दिल्ली पहुंचने और वहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद इन अफवाहों को और हवा मिली। बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देते हुए परमेश्वर ने मीडिया से कहा कि अंदर क्या बात हुई, यह किसी को नहीं पता। हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल वही पता है जो केसी वेणुगोपाल ने कहा है। मुझे बस इतना ही कहना है।

ममता बनर्जी के असंवैधानिक बयान पर एफआईआर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। शिकायत 20 मई को अधिवक्ता रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, बनर्जी ने दो टिप्पणियां कीं, एक 2025 में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान और दूसरी विधानसभा चुनावों से पहले धर्मतला में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान, जिनसे कथित तौर पर भारत और दुनिया भर में लाखों सनातनी हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंची। पुलिस ने बताया कि वकील ने यह भी आरोप लगाया कि ये बयान असंवैधानिक और भड़काऊ प्रकृति के थे। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि बनर्जी ने कहा था कि एक विशेष समुदाय चाहे तो पांच मिनट के भीतर दूसरे समुदायों को खत्म कर सकता है। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं की जाती।

केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर ईडी की रेड

तिरुवनंतपुरम। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में ईडी ने ये रेड की है जिसमें पिनाराई के घर और अन्य ठिकानों पर दबिश की दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और अन्य के आवासों पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 10 परिसरों पर, जिनमें राजधानी में विजयन का किराए का घर भी शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है कि वीणा थैकंडियिल भी वहीं रह रही हैं। ये तलाशी वीणा की आईटी कंपनी, एक्सालॉजिक साल्यूशंस से जुड़ी जाँच के सिलसिले में की गई थी।

बंगाल एसटीएफ ने तृणमूल विधायक को किया गिरफ्तार

कोलकाता। तृणमूल विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पिछले 13 दिनों से लापता थे। बंगाल एसटीएफ उनकी धरपकड़ के लिए पूरा जोर लगा रही थी। तृणमूल नेता को पुरी के 'ब्लू लिली' होटल से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह करीब तेरह दिनों से पुरी शहर में छिपे हुए थे। पुलिस का दावा है कि वो एक होटल में नहीं, बल्कि कई होटलों में ठहरे थे। आखिरकार बंगाल एसटीएफ ने उनका पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उनको ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद, दिलीप मंडल ने विजय जुलूस या जनसभा से विपक्ष के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां कीं। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों और संपत्तियों को जला दिया जाएगा और तोड़फोड़ की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा को वोट देने वालों या भाजपा के लिए काम करने वालों को बिष्णुपुर इलाके में रहने नहीं दिया जाएगा।

राहुल गांधी के बाद अमेठी में स्मृति ईरानी की दस्तक

अमेठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया दौरे के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी पहुंचने से जिले की सियासत फिर चर्चा में आ गई है। बुधवार को जिले की सीमा पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए। स्मृति ईरानी मुसाफिरखाना में आयोजित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से लगातार जनसंपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। उनके आगमन से भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। दौरे के दौरान वह सिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र के पूरे ठकुराइन मजरे मत्तेपुर गांव भी पहुंचीं। यहां भाजपा नेता रमेश तिवारी के भाई बृजेश तिवारी के निधन पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और कुछ समय तक परिजनों के बीच रहीं। राजनीतिक गलियारों में स्मृति ईरानी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अमेठी पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।

भारत की पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एमसीए) परियोजना के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी कर दिया है। यह प्रस्ताव तीन शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को भेजा गया है, जिनमें लार्सन एंड टुब्रो-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज-बीईएमएल शामिल हैं। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एएमसीए कार्यक्रम को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान परियोजना माना जा रहा है, जिसके 2030 के मध्य से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता की रीढ़ बनने की उम्मीद है। यह एक दो इंजन वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसमें उन्नत सेंसर प्रणाली, अंदरूनी हथियार रखने की सुविधा, कृत्रिम

बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक और नेटवर्क से जुड़ी युद्ध क्षमता जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 15 मई को श्री सत्य साईं जिले में 16 हजार करोड़ रुपये की एएमीए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की आधारशिला रखी। इसे भारत के रक्षा इतिहास का %ऐतिहासिक अध्याय% बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह पहल आंध्र प्रदेश के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आठ ड्रोन कंपनियां कुरनूल में ड्रोन सिटी स्थापित करने में मदद करेंगी।

छठी पीढ़ी के जेट की जरूरत?

इस साल मार्च में ससंद की रक्षा समिति ने कहा था कि आधुनिक युद्ध में तेजी से बदलाव हो रहा है और उन्नत लड़ाकू विमानों की जरूरत बढ़ रही है। चीन भी अपने छठी पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है और उसने इसके कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इसके अलावा, चीन अपने पांचवीं पीढ़ी के विमान पाकिस्तान के साथ साझा करने की तैयारी में है, जिससे भारत के लिए यह चुनौती और बढ़ जाती है।

रक्षा समिति के अनुसार, भारत अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एएमसीए) निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसका डिजाइन तैयार हो चुका है। भारतीय वायुसेना की योजना 2035 तक ऐसे छह स्क्वाड्रन शामिल करने की है, जिससे देश की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

भारत ने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर 110-120 केएन क्षमता का शक्तिशाली इंजन विकसित करने का फैसला किया है। यही इंजन भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। इस कदम से भारत की रक्षा तकनीक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी और विदेश पर निर्भरता कम होगी। अमेरिका की तरफ से एफ-35 की डिलीवरी के बाद उसके कई सहयोगियों को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिले हैं। हालांकि, कुछ और देश अपने पांचवीं पीढ़ी के मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान?

1. अमेरिका- मौजूदा समय में सिर्फ तीन देशों के पास पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बताई जाती है। इनमें सबसे आगे अमेरिका है, जिसके पास लॉकहीड मार्टिन कंपनी के एफ-22 रैप्टर और एफ-35 लाइटनिंग-II एयरक्राफ्ट मौजूद हैं।

2. चीन- पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कैटेगरी में चीन अपने पास दो फाइटर जेट्स होने का दावा करता है। इनमें से एक चेंगदू का जे-20 और दूसरा चेंगदू का ही जे-35 है। हालांकि, इनकी क्षमताओं को लेकर ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि जे-20 के हाई-स्पीड ट्रायल 2011 में शुरू कर दिए गए थे। हालांकि, इसे चीन की वायुसेना में मार्च 2017 में शामिल किया गया। वहीं, जे-35 फाइटर जेट कार्यक्रम 2007 से ही जारी है। इसे 2024 के एयरशो में दुनिया के सामने पेश किया गया। हालांकि, इसके परीक्षण अभी कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं।

3. रूस- अभी रूस के पास सिर्फ एक एसयू-57 एयरक्राफ्ट ही पांचवीं पीढ़ी का है। इसकी पहली उड़ान 2010 में दर्ज हुई थी। रूसी वायुसेना को 2020 में इस फाइटर जेट की डिलीवरी भी मिली थी। हालांकि, इसकी क्षमताओं का पूरी तरह दुनिया के सामने आना अभी बाकी है।

समाचार पचीसा
रायपुर, गुरूवार 28 मई 2026

कलेक्टर की समीक्षा बैठक हुआ सम्पन्न

किसानों से खाद-बीज का अग्रिम उठाव करने कलेक्टर ने की अपील

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले के किसानों से खाद-बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले के सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारण किया जा रहा है, जिसका अग्रिम उठाव किसान भाई करें। वर्तमान में सहकारी समितियों में यूरिया- 7197 मेट्रिक टन, डी.ए.पी. 1588 मेट्रिक टन, सुपर फास्फेट 4614 मेट्रिक टन, पोटाश 2663 मेट्रिक टन और एन.पी.के 6833 मेट्रिक टन का भण्डारण किया जा चुका है। डीएपी के विकल्प के तौर पर सुपर फास्फेट और एन.पी.के. उर्वरकों के उपयोग की सिफारिश कृषि वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। जिसके आधार पर इस समितियों से कृषकों को उर्वरक वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही समितियों के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी किसानों को वितरित किया जा रहा है, जिसका उपयोग बीजोपचार एवं खड़ी फसल में छिड़काव दोनों तरीके से किया जा सकता है। नैनो उर्वरकों के उपयोग से यूरिया और डी.ए.पी. के कम मात्रा के उपयोग की आवश्यकता होगी, यह नत्रजन और फास्फोरस तत्वों की पूर्ति करता है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद-बीज का उठाव करें। प्राय: यह देखा जाता है कि कई किसान बारिश शुरू होने के बाद खाद का उठाव करते हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ने पर आपूर्ति संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। किसान भाईयों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में मानसून प्रारंभ होने वाला है और इसी के साथ खरीफ कार्य भी शुरू हो जाएंगे।

पहली बार गोगुंडा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

- **कभी नक्सली घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहने वाले गोगुंडा गांव में अब विकास और उम्मीद की नई कहानी लिखी जा रही है.**

सुकमा। जिले के गोगुंडा गांव के लोग दशकों तक नक्सल दहशत के साए में जीने को मजबूर रहे हैं। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव में नक्सलियों के कब्जे और भय के कारण सड़क, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं कोसों दूर थीं। कई ग्रामीण ऐसे भी थे, जिन्होंने जीवनभर डॉक्टर तक नहीं देखा। सुरक्षा कैंप खुलने के बाद प्रशासन की पहुंच धीरे-धीरे गांव तक बनने लगी है। स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पहली बार मोतियाबिंद के मरीजों को लेने गोगुंडा पहुंची।

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया। नेत्र सहायक अधिकारी सचिन वैध ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की। 10 ग्रामीणों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिसके बाद सभी मरीजों को बेहतर इलाज और ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल सुकमा लाया गया। गोगुंडा के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि गरीबी, दूरी और नक्सली भय के कारण आंखों का इलाज नहीं करा पा रहे थे। गांव से अस्पताल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था।

रास्ते में घने जंगल, पहाड़ और बारिश के दिनों में उफनते नाले ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देते थे। ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी और कैंप स्थापित होने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग, राशन, सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं अब गांवों तक पहुंचने लगी हैं।

जो गांव कभी नक्सलियों की वजह से प्रशासन के लिए चुनौती माने जाते थे, वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही हैं। सुकमा की टोटल पापुलेशन टारगेट - 293375 टोटल स्क्रीनिंग - 251999 टोटल सस्पेक्ट - 4418 टोटल मरीजों को रेफर किया गया है - 5881 स्वस्थ बस्तर अभियान का उद्देश्य स्वस्थ बस्तर अभियान का उद्देश्य ही यही है कि दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को उनके गांव के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी ग्रामीण सिर्फ दूरी या डर की वजह से इलाज से वंचित न रहे।जहां कभी बंदूकें और बारूद विकास का रास्ता रोकते थे, वहीं अब एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीमें उम्मीद लेकर पहुंच रही हैं। यह बदलाव केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों के जीवन में लौटती विश्वास की कहानी है, जो दशकों तक भय और उपेक्षा में जीते रहे।

कार्यालय में शराब बोतल के साथ दिखे नगर पंचायत सीएमओ

- **बेमेतरा कलेक्टर ने कहा- जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई के लिए शासन को भेज रहे**

बेमेतरा। जिले के दाढ़ी नगर पंचायत के ष्ट्स्ह आर के ध्रुव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने कार्यालय में ही शराब को बोतल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा के एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने दाढ़ी सीएमओ को इस मामले में शराब की बोतल और नेम प्लेट का जिक्र करते हुए नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। वहीं कलेक्टर ने भी मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि दाढ़ी नगर पंचायत अपने कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहां के कई निर्माण कार्य पूरे नहीं हो रहे। अधूरे निर्माण के लिए लगातार यह नगर पंचायत विवादों में रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में सूचना के अधिकार नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है। लोगों को जानकारी नहीं दी जाती। वहीं पहले भी फर्नीचर खरीदी के नाम पर लाखों के घोटाले की जांच अभी भी जारी है। इस बीच अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें दाढ़ी नगर पंचायत के सीएमओ आर के ध्रुव शराब बोतल के साथ दिख रहे हैं। वे नगर पंचायत कार्यालय में ही रहते हैं और यह वीडियो वहीं से वायरल हुया है। इस मामले में अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि सीएमओ एवं तहसीदार को जांच के आदेश दिए गए हैं जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

भूपेश बघेल का रोड शो, गुरु खुशवंत साहेब ने बीजेपी की कमान संभाली, आप की भी दस्तक

जांजगीर चांपा। बम्हनीडीह चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के साथ अध्यक्ष पद के लिए पांच दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी पार्टी, चुनाव प्रचार कर एक दूसरे के खिलाफ खुल कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत बुधवार को बम्हनीडीह में रोड शो करेंगे। जांजगीर चाम्पा जिले में नौतपा की गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है, वहीं बम्हनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ 15 पार्षदों के लिए राजनीति भी गरमा गई है। नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल

अपना दबदबा दिखाने में जुटे हैं। बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मंत्री खुशवंत साहेब को कमान सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को चुनाव प्रभारी बनाया और आप पार्टी ने भी चुनाव कैम्पनिंग के लिए प्रियंका शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी पार्टी चुनाव के लिए अपने अपने तरीके से वोट मांगने में जुटी हैं। आप पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरूपयोग करने और दारू मुर्गा बांट कर मतदाता को खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रति पक्ष चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों के साथ बम्हनीडीह में रोड शो कर जनता से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जय सिंह अग्रवाल ने बीजेपी के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को पहली बार विधायक बनने की बधाई दी और बीजेपी के मंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से नगर पंचायत चुनाव की कमान संभाल रहे मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी बम्हनीडीह के वार्डों में जाकर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्ग मतदाताओं से मिल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के साथ जाने से नगर का विकास होना तय बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के रोड शो को लेकर कहा कि पांच साल सरकार में रह कर कांग्रेस ने जनता का शोषण किया और प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, जिसके परिणामस्वरुप प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कार दिया। उन्होंने बम्हनीडीह में भी बीजेपी को ही जीत मिलने का दावा किया। बहरहाल बम्हनीडीह में चुनावी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। कांग्रेस ने बम्हनीडीह क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ बताते हुए अपने विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए लगाया है।

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप

- **पीसीसी सचिव ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल**

राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव विधानसभा में मतदाता सूची से नाम गायब होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम बिना किसी सूचना के मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं।

मेहुल मारू ने एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए बताया था कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा सरकार और निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।

पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस नेता मारू ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम, विपक्ष के लोगों के नाम व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे हैं। मारू ने कहा कि हमारे घर से 6 लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरे थे, जिनमें से मेरा और मेरी पत्नी का नाम काट दिया गया।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने एसईसीएल के कार्यों की समीक्षा की

बिलासपुर। कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार सतीश चन्द्र दुबे ने मंगलवार को एसईसीएल के एक दिवसीय दौरे के दौरान कंपनी के कार्यों एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल परिवर्तन एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ एवं लोकार्पण भी किया। एसईसीएल मुख्यालय पहुँचने पर कोयला मंत्री श्री दुबे ने एसईसीएल मुख्यालय परिसर स्थित कोयला श्रमिक स्मारक पर माल्यार्पण कर कोयला श्रमिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र निर्माण एवं देश की ऊर्जा सुरक्षा में उनके अमूल्य योगदान को नमन किया।

इसके पश्चात एसईसीएल मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मंत्री ने कोयला उत्पादन, डिस्पैच, गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा, कोल गैसीफिकेशन, माइन क्लोजर, पर्यावरणीय पहलों, डिजिटलीकरण, सीएसआर गतिविधियों तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन, निदेशकगण, सीवीओ, विभागाध्यक्ष, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री ने सुरक्षित एवं सतत खनन को बढ़ावा देने, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा आधुनिक तकनीकों के अधिकाधिक उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एसईसीएल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से कोयलांचल के अंतिम व्यक्ति तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कोल इंडिया द्वारा अब तक किए गए 100 मिलियन टन उत्पादन में एसईसीएल ने 26.86 मिलियन टन के सर्वाधिक योगदान के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एसईसीएल निरंतर प्रतिबद्ध है।समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मंत्री द्वारा ई-डाडास (डिज़ाइन एंड ड्राविंग्स एप्रूवल इन एसईसीएल) पोर्टल एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब पर्ची के लिए नहीं भटकना होगा

सरगुजा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब इलाज कराने के लिए पर्ची की लम्बी कतार में नहीं लगना होगा। एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक बार बार नहीं भटकना पड़ेगा। अब आप आभा एप के जरिये अपना अप्वाइंटमेंट पहले ही बुक कर सकते हैं और पर्ची भी ऑनलाइन ही जनरेट कर सकते हैं। आपके जीवन भर की सभी रिपोर्ट्स और पर्ची हमेशा के लिए आनलाइन उपलब्ध रहेगी। डिजिटल हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लगातार नई पहल कर रहा है। अस्पताल में 'आभा' के माध्यम से मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इससे न केवल मरीजों को लम्बी लाइनों से राहत मिल रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड भी सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संरक्षित हो रहे हैं। आभा एक 14 अंकों की विशिष्ट हेल्थ आईडी है, जिसे आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के माध्यम से बनाया जाता है। इस डिजिटल पहचान के जरिए मरीजों का पूरा उपचार रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। मेडिकल

कन्हर नदी के तट पर भव्य गंगा आरती में उमड़े लोग

बलरामपुर। रामानुजगंज में कन्हर नदी के तट पर भव्य गंगा दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। बनारस के पंडितों ने महामाया मंदिर के पास कन्हर मैया की महाआरती की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जीवनदायिनी मानी जाने वाली कन्हर नदी के तट पर इस वर्ष गंगा दशहरा का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। महामाया मंदिर के पास स्थित कन्हर घाट पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विशेष रूप से आए विद्वान पंडितों ने पूरे विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ कन्हर मैया की भव्य महाआरती संपन्न कराई। इस दौरान कन्हर नदी के तट को दीपों से सजाया गया था, जिससे पूरा नजारा बनारस के घाटों जैसा दिव्य और विहंगम प्रतीत हो रहा था। इस पावन अवसर पर कन्हर मैया के दर्शन और आरती में शामिल होने के लिए पूरे रामानुजगंज शहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना

गौरेला पेंड्रा मरवाही। आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। कलेक्टर कार्यालय (राहत शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक-04 में 1 जून 2026 से जिला आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 07751-221004 निर्धारित किया गया है। आदेश के तहत डिप्टी कलेक्टर आकांक्षा पाण्डेय को नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, इनका मोबाइल नम्बर 7869649251 है। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख दशोदा आर्मो को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनका मोबाइल नम्बर 6265606459 है। राजस्व निरीक्षक माधुरी राठौर को नियंत्रण कक्ष की सतत निगरानी एवं राहत कार्यों में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की हैं। पेंड्रारोड (गौरेला) तहसील के लिए तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल नियुक्त है।

जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में लाठी डंडे चले

कबीरधाम। भोरमदेव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी हाथीडोब में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर बैठे। घटना में दो महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह झाड़ू साहू की बाड़ी में लगे लकड़ी के रुंधान को पड़ोसी लक्ष्मण साहू और उसके परिवार द्वारा अपना बताकर तोड़ा जा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में झाड़ू साहू, उनकी पत्नी रुक्मणी साहू, लक्ष्मण साहू और उनकी पत्नी हेमलता साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

एमएलए ने कोंडागांव में विभिन्न निर्माण कार्यों का लिया जायजा

कोण्डागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक सुश्री लता उसेंडी ने मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के साथ शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण एवं पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौपाटी मैदान, डीएनके कॉलोनी, बाजारपारा स्कूल, गांधी वार्ड स्थित पीएमश्री स्कूल तथा निर्माणाधीन सखी सेंटर भवन का जायजा लेकर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए हाउसिंग बोर्ड एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। विधायक ने कहा कि पुनर्विकास कार्यों के माध्यम से शहर को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधायुक्त बनाया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

कोरिया के किसानों को नहीं मिल रहा खाद

सहकारी समितियों की कार्यशैली से लोग नाराज

कोरिया। खरीफ की खेती का सीजन चल रहा है। किसान डीजल और खाद के लिए लगातार भटक रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ग्राम जिल्दा में खाद को लेकर किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी। किसानों का आरोप था कि ग्राम जिल्दा के आदिम जाति सहकारी समिति से खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसानों की शिकायत पर स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन की टीम पहुंची। जांच में किसानों के आरोप सही पाए गए। आदिम जाति सहकारी समिति में सामने आए उर्वरक घोटाले के बाद जिला प्रशासन भले ही सख्ती और पारदर्शिता की बात कर रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी कई सहकारी समितियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। किसानों की मानें तो जिले के कुछ क्षेत्रों में आज भी खाद वितरण को लेकर

अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पूर्व में ही किसानों ने आरोप लगाया था कि लंबे समय से जिल्दा सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा खाद की कृत्रिम कमी बताई जाती रही, जबकि शासन स्तर से पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा था। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से खेती-किसानी प्रभावित हुई और कई किसानों को निजी दुकानों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीदना पड़ा। जिल्दा में खाद घोटाला सामने आने के बाद जिले की सभी समितियां पूरी तरह नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं, इसको लेकर किसानों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। किसानों कि मानें तो सोनहत और बैकुंठपुर क्षेत्र की कुछ सहकारी समितियों में अब भी खाद वितरण को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही। आरोप है कि किसानों को कभी स्टॉक खत्म होने का हवाला दिया जाता है तो कभी वितरण प्रक्रिया में देरी कर उन्हें परेशान किया जाता है। किसानों का कहना है, खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन समितियों में समय पर उर्वरक नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि समिति स्तर पर जानकारी स्पष्ट नहीं दी जाती, वास्तविक स्टॉक की स्थिति भी किसानों से छिपाई जाती है।

जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग जारी है। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों के तहत खाद वितरण सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य से जिले के सभी समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर केपीसीसी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई।

कोरिया कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

सरगुजा के केरजू धान खरीदी घोटाले की जांच पर ही उठे सवाल

किसानों ने 2 चहेतों को बचाने का लगाया आरोप

सरगुजा। जिले के पेटला सहकारी बैंक के केरजू धान खरीदी केंद्र में हुए घोटाला मामले की जांच ही संदेह के दायरे में हैं। किसानों ने जांच दल पर ही गलत जांच कर कुछ लोगों को बचाने का आरोप लगाया है।

इसे लेकर केरजू के ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर, सहकारी बैक के सीईओ और कमिश्नर सरगुजा से शिकायत की है और दोबारा जांच कराने की मांग की है। ग्रामीण निरंकार यादव का कहना है कि जब मामले में 10 लोग शामिल हैं, तो कार्रवाई सिर्फ 8 लोगों पर ही क्यों की गई है।

2 अन्य कर्मचारी जिनकी आईडी से लेन देन हुआ है उन पर स्न्ह्रुक्र्यों नहीं की गई, उन्हें जांच से क्यों बाहर रखा गया? वहीं

मामले में केरजू समिति के प्रबंधक जिसके माध्यम से सीधे भ्रष्टाचार किया गया उसका नाम भी जांच में नहीं है।

क्योंकि वो अपनी जान दे चुका है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है की प्रबंधक नहीं है लेकिन उसने जो करोडों की संपत्ति बनाई है वो तो है, प्रशासन को उसे नीलाम कर घोटाले की भरपाई करनी चाहिए।

इधर सहकारी बैंक के ष्ट्श्वह्न ने कहा कि इस मामले में जांच दल कार्यालय कलेक्टर से गठित किया गया था, और जांच रिपोर्ट के आधार पर वहीं से कुल 8 लोग पर अपराध दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीणों की जो शिकायत है उस पर दोबारा ऑडिट कराने को भी कहा गया है। दरअसल, सीतापुर क्षेत्र के पेटला सहकारी बैंक के तहत आने वाले केरजू धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली। प्रबंधक की मौत के बाद यहां किसानों ने बवाल कर दिया। किसानों ने उनके खाते से गलत तरीके से लोन की राशि आहरण करने के आरोप लगाये। शिकायत के बाद कलेक्टर सरगुजा ने एक जांच दल बनाया और जांच कराई गई।

संक्षिप्त समाचार

आईएफएस अरूण पांडेय बने नए पीसीसीएफ, श्रीनिवास राव की लेंगे जगह

रायपुर। राज्य सरकार ने आईएफएस अरूण पांडेय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के तौर पर नियुक्त कर दिया है। मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वह व्ही। श्रीनिवासन राव की जगह लेंगे। दरअसल, प्रमुख पीसीसीएफ व्ही. श्रीनिवास राव 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में नए पीसीसीएफ के लिए डीपीसी की बैठक हुई थी। इसमें अरूण पाण्डेय, अनिल साहू और कौशलेंद्र कुमार के नाम पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद अरूण पाण्डेय के नाम पर मुहर लगी। अरुण कुमार पांडेय 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह मूल रूप से अंबिकापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने तीसरे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। उनके पास राजनांदगांव, कोरबा और जशपुर जैसे जिलों में लंबे वक्त तक डीएफओ के रूप में काम करने का अनुभव है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अहम पदों पर भी रहे हैं।

विश्व रक्तदान दिवस पर लगेगा शिविर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक

रायपुर। कलेक्टर एवं रेडक्रॉस जिला शाखा अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की जिला प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में सोसायटी की सदस्यता एवं समाजसेवा गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2015 से अब तक जिले में 6237 सदस्य बने हैं। इनमें 24 संरक्षक, 9 उपसंरक्षक, 1256 आजीवन सदस्य और 4948 वार्षिक सदस्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4616 नए सदस्य जुड़े। वहीं मार्च 2026 से 25 मई तक वर्ष 2026-27 के लिए 1619 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें 3 संरक्षक, 2 उपसंरक्षक, 262 आजीवन और 1352 वार्षिक सदस्य हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस जरूरतमंदों की मदद का सशक्त माध्यम है, इससे अधिक से अधिक लोगों को जोडना़ जरूरी है। बैठक में जून माह में वृक्षारोपण कार्यक्रम, जुलाई में स्कूलों के जेआरसी विद्यार्थियों के लिए भव्य कार्यक्रम, प्रबंध समिति सदस्यों का प्राथमिक उपचार व सी.पी.आर. प्रशिक्षण तथा विश्व रक्तदान दिवस पर जून में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, रेडक्रॉस चेयरमेन श्री राजू शर्मा, सीएमएचओ सह सचिव डॉ. मिथिलेश चौधरी, वाईस चेयरमेन डॉ. प्रीति नारायण, कोषाध्यक्ष सुश्री पल्लवी पाण्डेय समेत प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

पद्मश्री गोडबोले दंपती का महाराष्ट्र मंडल में सम्मान आज

रायपुर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सोमवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त करने के बाद डॉ. रामचंद्र गोडबोले और डॉ. सुनीता गोडबोले दंपती को महाराष्ट्र मंडल गुरुवार, 28 मई को शाम 06:30 बजे सम्मानित करने जा रहा है। मंडल के य.गो. जोगलेकर स्मृति छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आयोजित होने वाले विनायक दामोदर सावरकर जयंती समारोह में डॉ. गोडबोले दंपती सम्मानित किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर दंपती अपने 35 वर्षों से बस्तर के अबूझमाड़ में शोषित पीड़ित और बीमार आदिवासियों का निन्शुल्क इलाज करने से लेकर वहां इलाज को लेकर फैली भ्रांतियों और उन्हें दूर करने को लेकर किए गए भगीरथ प्रयास के बारे में चर्चा भी करेंगे। उपाध्यक्ष गीता दलाल ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र मंडल में गुरुवार को वीर सावरकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर वीर सावरकर पर आमंत्रित किए गए लेख के आधार पर निर्णायक परिणाम तय कर विजेताओं, उप विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे, जिन्हें कार्यक्रम के दौरान ही पुरस्कृत व प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

दिवंगत रूपनारायण सिन्हा के घर पहुंचकर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार सुबह योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के कबीर नगर स्थित निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रूपनारायण सिन्हा की अचानक तबियत बिगड़ गई। इस बीच उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। आज कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रूपनारायण से उनका बहुत पुराना संबंध रहा है। वे लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए थे और उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी बेहद आत्मीय रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को संबल प्रदान करें और दिवंगत रूपनारायण सिन्हा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

छत्तीसगढ़ में अनुपयोगी सरकारी जमीनों का होगा कायाकल्प: मुख्य सचिव

विभागों, निगम-मंडलों और बोर्ड की खाली जमीनों का होगा व्यवस्थित विकास, बनेगा डिजिटल लैंड बैंक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से चिन्हित की गई भूमियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि वर्तमान में अनुपयोगी पड़ी सरकारी जमीनों से न तो शासन को कोई आय हो रही है और न ही

जनता को इसका लाभ मिल रहा है। इस रिडेव्हलपमेंट योजना से जहां शहरों को एक नियोजित विकास मिलेगा, वहीं शासकीय परिसंपत्तियों का मूल्य भी कई गुना बढ़ जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से खाली पड़ी या अतिक्रमण की आशंका वाली सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उनका व्यावसायिक व जनहित में बेहतर उपयोग किया जाएगा। शासकीय विभागों के अंतर्गत आने वाली सभी खाली जमीनों का एक केंद्रीय डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। मैपिंग के जरिए हर प्लॉट की सटीक लोकेशन, रकबा (क्षेत्रफल) और वर्तमान स्थिति का डेटा जीआईएस (तद्रूस) मैपिंग ऑनलाइन दर्ज होगा। शहरों में प्राइम लोकेशन पर स्थित खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और नए सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा। बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा।

ग्रामीण इलाकों की जमीनों पर कृषि, उद्यानिकी, आधुनिक वेयरहाउस या कौशल विकास केंद्र प्रस्तावित किए जाएंगे। बड़ी जमीनों के सुनियोजित विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। योजना के तहत ऐसे शासकीय भवनों और परिसरों को चिन्हित किया जाएगा जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और जिनकी मरम्मत करना वित्तीय दृष्टि से फायदेमंद नहीं है। ऐसी जगहों पर पुरानी संरचनाओं को हटाकर शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सरकारी विभागों या उनके उपक्रमों के लिए नए और आधुनिक निर्माण किए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित जमीनों पर तत्काल फेंसिंग (घेराबंदी) की जाएगी और शासकीय स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा। इन जमीनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निगरानी रखेंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, एनआरडीए के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी संभागायुक्त व कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

भीषण गर्मी में सतर्कता और संवेदनशीलता बरतें, जरूरतमंदों का सहारा बनें: साय

■ **मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

तेंदूपत्ता अग्निकांड पर वन मंत्री का बड़ा एक्शन

बीजापुर डीएफओ हटाए गए, अनुभवी अधिकारी की तैनाती, घटना की होगी निष्पक्ष जांच

रायपुर/बीजापुर। बीजापुर जिले में हुए तेंदूपत्ता अग्निकांड को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचाने वाली इस गंभीर घटना पर मंत्री कश्यप ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीजापुर के वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) रमेश कुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर में संबद्ध किया गया है।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर तेंदूपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन में अनुभवी अधिकारी जाधव सागर रामचंद्र को बीजापुर का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को शासन का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि वनवासियों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वन मंत्री केदार कश्यप ने दो टूक कहा कि तेंदूपत्ता केवल वन उपज नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी और वनवासी परिवारों की आजीविका का आधार है। उनकी मेहनत और अधिकारों की रक्षा

करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी स्तर की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री कश्यप ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, समयबद्ध और तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके।

नवनियुक्त डीएफओ जाधव सागर रामचंद्र वर्तमान में राज्य लघु वनोपज संघ में पदस्थ हैं और तेंदूपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में उनके प्रभावी कार्य और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए शासन ने बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2026 को बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक निजी गोदाम में भीषण आग लगने से विभिन्न समितियों का संग्रहित तेंदूपत्ता जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है। वास्तविक नुकसान का विस्तृत भौतिक सत्यापन वर्तमान में जारी है।

शासन ने घटना के कारणों, गोदामीकरण प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों के पालन, अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका तथा संभावित वित्तीय क्षति सहित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वन संपदा की सुरक्षा और आदिवासी हितों की रक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वायरल ऑडियो पर सियासत: विधायक रेणुका सिंह ने बताया एआई जनरेटेड

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल बोले- जो दिल में था, वह जुबां पर आ गया

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक बिसात में दो वायरल ऑडियो ने आग लगा रखी है। वायरल ऑडियो भाजपा विधायक रेणुका सिंह का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विधायक रेणुका और उनकी पार्टी से खीचतान को लेकर हमला बोला है।

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरे क्लिप में जिला महामंत्री मनोज साहू के खिलाफ टिपण्णी की गई, जिन्होंने सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री के सामने विधायक रेणुका सिंह की शिकायत की थी। फिर क्या था राजनीति में भूचाल आ गया।

इस पूरे मामले में विधायक रेणुका सिंह ने दोनों ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया। इस पर तंज कस्ते हुए पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि आज तक वीडियो में एआई जनरेटेड तकनीक देखी थी, जहां किसी के चेहरे के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन अब अगर किसी की आवाज में कोई और बोल रहा है और उसे एआई कहा जा रहा है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो तत्काल एफआईआर होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

भूपेश बघेल ने कहा कि रेणुका बहुत पुरानी साथी हैं। लंबे समय तक हम विधानसभा में साथ रहे। वे लोकसभा गईं, केंद्रीय मंत्री भी रहीं और अब फिर विधानसभा में हैं। लेकिन आजकल वे विधानसभा नहीं आतीं, नाराज रहती हैं। मुझे तो लगता है कि जो उनके दिल में था, वही जुबां पर आ गया। इस वायरल ऑडियो के मामले में विधायक रेणुका सिंह और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। फिलहाल कांग्रेस इस घटनाक्रम को सत्ताधारी दल में बड़ा फूट पैदा करने की कोशिश में है। वहीं जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर मनोज साहू को 22 मई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था।

सिंहदेव और दीपक बैज का अनशन खत्म

■ **तीन मांगों पर प्रशासन से मिली सहमति**

सूरजपुर। शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के बीच सूरजपुर जिला कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का अनशन खत्म हो गया है। प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और फिर चर्चा के बाद नारियल पानी पीकर अनशन खत्म किया।

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के बीच जिले के महामंत्री नागेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करने के विरोध में टीएस सिंहदेव और दीपक बैज मंगलवार शाम से आमरण अनशन पर बैठे थे। प्रशासन की मान मनौव्वल की

कोशिशें चलती रहीं। स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं की तीन सूत्रीय मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद अनशन खत्म हुआ।

कांग्रेस नेताओं ने कॉउंटर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। महामंत्री नागेन्द्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले की विवेचना डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा विश्रामपुर थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तीन मांगें पूरी होने के बाद सिंहदेव और बैज ने अनशन खत्म किए। आंदोलन समाप्त करते हुए दीपक बैज ने कहा कि अंततः न्याय की जीत हुई। पुलिस एवं प्रशासन ने कांग्रेस की सभी मांगें मान ली है। टीएस सिंहदेव की अनुमति से आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है।

शिवनंदनपुर नगर पंचायत की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया है। इसके विरोध में टीएस सिंहदेव आमरण अनशन पर बैठे हैं, जबकि दीपक बैज भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश के कांग्रेसजन चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। थानेदार का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार आती-जाती रहती है। किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी।

डी-लिस्टिंग के समर्थन में उतरे अरविंद नेताम

■ **कहा- देर-सवेर होकर रहेगी, यूडी मिंज ने मांग पर जताया विरोध**

रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम के मंच पर डी-लिस्टिंग की मांग के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अन्य धर्म अपना चुके लोगों को एसटी सूची से बाहर करने की मांग की जा रही है। इस बहस में एक और समर्थन तो दूसरी तरफ खुलकर विरोध भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ से इस मांग का वनवासी सुरक्षा मंच के बैनर तले पूर्व मंत्री गणेशराम भगत और सांसद भोजराम नाग नेतृत्व कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविन्द नेताम भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वह नहीं जा पाए। उन्होंने डी-लिस्टिंग को लेकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर तैयारी की गई है और समाज की भावनाओं के अनुरूप यह मांग लगातार मजबूत हो रही है। देर-सबेर डी-लिस्टिंग होकर

रहेगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कड़े कानून की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं।

अरविन्द नेताम ने कहा कि यह एक संवेदनशील विषय है, जो धीरे-धीरे राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

जशपुर में डी-लिस्टिंग की मांग का विरोध का माहौल है। पूर्व संसदीय सचिव यूडी मिंज और गीता उरांव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। यूडी मिंज का कहना है कि डी-लिस्टिंग की मांग संविधान की भावना के विपरीत है और इसे अनावश्यक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद भी आदिवासी समाज की परंपराएं, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान खत्म नहीं होती है। जशपुर जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है और समाज की पहचान उसके सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस सरकार के दौरान रौतिया समेत अन्य समाजों को आदिवासी वर्ग में शामिल करने के लिए टीआरआई के माध्यम से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था।

आसान भाषा में डी-लिस्टिंग यानी लिस्ट से बाहर करना। आदिवासियों की इस मांग के सन्दर्भ में डीलिस्टिंग का मतलब, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है।

केंद्र सरकार से आदिवासी नेता संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (article 342) राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति (एसटी) माने जाने वाली जनजातियों या आदिवासी समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव (छ.ग)

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना क्रमांक-08

क्रमांक / 837 / वलेलि / ग्रायांसेवा/2026-27 राजनांदगांव, दिनांक 25.05.2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से पंजीकृत एकीकृत पंजीयन प्रणाली से प्रपत्र 'ए' में दर्शित निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दर प्राप्त करने आनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	निविदा आमंत्रण	निविदा कार्यालय में पहुचने कि अंतिम तिथि
विकास खण्ड क्षेत्रीय जोनल निविदा 2026-27 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग डोंगरगांव अंतर्गत विभिन्न मदो में स्वीकृत 30.00 लाख से कम लागत के भवन एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य	40.00	द्वितीय बार	04.06.2026

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबपोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 26.05.2026 से देखी जा सकती है। निविदा कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 04.06.2026 सायं 5.30 तक है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग- राजनांदगांव

जी-262701006/5

चुनावी हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी हलचल तेज

पवन

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो विधायकों रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा की विधानसभा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात ने नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और अंदरूनी चर्चा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को दोनों विधायक विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिलने पहुंचे थे। उसी समय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। दरअसल, कुछ दिन पहले भी रितब्रत बनर्जी की दिल्ली के पुराने बंग भवन में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान दोनों नेताओं को बातचीत और मुस्कुराते हुए देखा गया था, जिसके बाद से ही बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही थीं। रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा हाल के दिनों में टीएमसी के भीतर खुलकर अपनी राय रखने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं। चुनाव में पार्टी की हार के बाद हुई एक बंद कमरे की बैठक में दोनों नेताओं ने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठाए थे। बताया गया कि उन्होंने प्रचार अभियान और नेतृत्व के फैसलों पर भी नाराजगी जताई थी। इसी वजह से विधानसभा में हुई ताजा मुलाकात को सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। हालांकि बाहर आने के बाद दोनों नेताओं ने किसी भी राजनीतिक महत्व से इनकार किया। रितब्रत बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि अचानक मंगलवार को ही मिलने क्यों पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि पहले मौका नहीं मिल पाया था। वहीं संदीपन साहा ने भी कहा कि यह सिर्फ संयोग था। उन्होंने कहा कि वे नए विधायक के तौर पर अध्यक्ष से मिलने गए थे और संयोग से मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ राजनीति कर चुके हैं, लेकिन इस मुलाकात का कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में इस तरह की मुलाकातें अक्सर बड़े संकेत देती हैं, खासकर तब जब संबंधित नेता अपनी ही पार्टी से असहज दिखाई दे रहे हों। रितब्रत बनर्जी ने यह भी खुलासा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी विधायकों को प्रशासनिक समीक्षा बैठकों में शामिल करने की बात दोबारा उठाई। उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन अलग-अलग चीजें हैं और अगर विपक्षी जनप्रतिनिधियों को विकास संबंधी बैठकों में बुलाया जाता है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर 15 साल में कोई काम नहीं हुआ तो अब उसे सुधारने में क्या दिक्कत है? इस बयान को भी राजनीतिक हलकों में खास संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। रितब्रत बनर्जी ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह पहले वामपंथी सांसद थे तब उन्हें प्रशासनिक बैठकों में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन बाद में टीएमसी सांसद रहने के दौरान उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डीएमके और एआईएडीएमके राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद राज्य के हितों के लिए एकजुट हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना सही नहीं होता।

ट्रम्प प्रशासन से पूरी तरह तंग आए अमरीकी

दरबारा सिंह काहलों

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के समय हर कोई नेता और राजनीतिक दल देश के मतदाताओं को दिन में तारे दिखाने के बड़े-बड़े वादे करते हैं। वे उनके जीवन को अप्रत्याशित स्वर्ग जैसी सुविधाओं से लबालब सराबोर करने के दावे पर दावे ठोकते हैं। अमरीका जैसी लोकतांत्रिक महाशक्ति के भीतर भी राष्ट्रपति चुनावों के समय विभिन्न पार्टियों से संबंधित नेता ऐसे ही वादे करते देखे जाते हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हमेशा ऐसे वादों और हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क देखा जाता है।

2024 में 47वें अमरीकी राष्ट्रपति के चुनावों में वर्तमान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमरीकियों से बहुत बड़े-बड़े वादे किए। उनमें सबसे बड़ा वादा यह था कि वह विश्व के इतिहास में अमरीका को फिर से एक महान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। परिणामस्वरूप, धड़ाधड़ अमरीकी युवा रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने लगे। निश्चित रूप से उन युवाओं ने ट्रम्प की जीत में अहम भूमिका निभाई।

वादा खिलाफी : 21 जनवरी, 2025 को सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने लोगों से किए गए वादों से बिल्कुल पीठ फेरकर अपने और अपने पूंजीपति मित्रों के मंसूबों को पूरा करने की ओर आंखें मूंदकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पूरे विश्व को अमरीकी आर्थिक जकड़ में बांधने के लिए भारी-भरकम और डरावनी आयात-निर्यात संबंधी टैरिफ नीति लागू करने का ऐलान किया, जो 'ट्रम्प टैरर टैरिफ' के रूप में बदनाम हो रही है। इसके अलावा पड़ोसी सांझेदार कनाडा को अमरीका का 51वां राज्य बनाने, ग्रीनलैंड, पनामा नहर और गाजा पर कब्जे के पागलपन भरे घोषणापत्रों, इसराईल के शैतान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आत्मघाती जाल में फंसकर ईरान पर हमले के बाद आज अमरीका के हालात ये हैं कि 'द इकोनॉमिस्ट' सर्वे के अनुसार, 18 से 29 साल के युवा उनके वर्तमान प्रशासन से बुरी तरह नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अंधकारमय भविष्य के कारण और आईस फैडरल एजेंसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते उनकी लोकप्रियता, जो जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के समय 45 प्रतिशत थी, अब गिरकर 25 से 33 प्रतिशत के बीच रह गई है।

निरपेक्ष सीनेटर बर्नी सैंडर्स के अनुसार, राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में पहले दिन से ही ट्रम्प अमरीकियों को भरोसा देते देखे जा रहे थे कि वह देश में महंगाई खत्म कर देंगे और अमरीका को फिर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बना देंगे। लेकिन अमरीका और इसके लोगों की बदकिस्मती यह है कि आज के ट्रम्प प्रशासन में गैस 28.4 प्रतिशत, हवाई किराया 20.7 प्रतिशत, एनर्जी 17.9 प्रतिशत, बीफ और वील (बछड़े का मांस) 14.8 प्रतिशत महंगे हो चुके हैं। 'न्यूजवर्क टाइम्स' और सिएना कॉलेज सर्वेक्षण ने ट्रम्प के दृष्टिहीन, एकाधिकारवादी, तानाशाह और मनमाने नेतृत्व के कारण अमरीकी लोगों में उनकी लगातार घटती लोकप्रियता को बेनकाब करके रख दिया है। इसके अनुसार 63 प्रतिशत लोगों ने उनके प्रति नाराजगी जाहिर की है, दो-तिहाई अमरीकी ईरान के खिलाफ युद्ध के उनके फैसले को गलत मानते हैं। इससे महंगाई बढ़ने के कारण पूरे देश के अंदर त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसी समय देश के अंदर मध्यावधि चुनावों की तलवार ट्रम्प प्रशासन पर लटक रही है। लोग उनकी रिपब्लिकन पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। इस समय राजनीतिक स्थिति यह है कि डैमोक्रेटिक पार्टी 10 प्रतिशत आगे चल रही है।

ट्रम्प का झूठ : ट्रम्प के 45वें राष्ट्रपति के शासन और वर्तमान 47वें राष्ट्रपति के शासन के बीच विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि वह हर रोज 21 झूठ अमरीका और विश्व समुदाय के आगे परोसते हैं। अप्रैल 4, 1949 में 12 देशों पर आधारित, यूरोप से उत्तरी अमरीका तक के क्षेत्र को तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तारवाद और सैन्य शक्ति से बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो संगठन गठित किया गया था। महाशक्ति के रूप में अमरीका को बाकी नाटो देशों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन पिछले 7 दशकों में भू-राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी हैं। एक तो ट्रम्प नाटो सहयोगियों को अमरीका पर अनावश्यक बोझ समझते आ रहे थे और दूसरा, उन्होंने इन पर भी मनमर्जी से टैरिफ थोपना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, उनके एकाधिकारवादी व्यवहार से तंग आकर नाटो सहयोगियों ने ईरान युद्ध में उनका साथ देने से इंकार कर दिया। जर्मनी से चिढ़े हुए ट्रम्प द्वारा अभी-अभी 5 हजार सैनिक वापस बुलाने की कार्रवाई ने अमरीका और नाटो सहयोगियों के बीच बढ़ते अंतर को उजागर कर दिया है।

ट्रम्प प्रशासन अमरीकियों को झूठ परोस रहा था कि ईरान के साथ युद्ध के समय उसका खर्च 29 बिलियन आया है, जबकि स्टीफन सेल्वर रिपोर्ट के अनुसार, जो कि क्विंसी संस्था से संबंधित है, 60 दिवसीय युद्ध का खर्च 71 बिलियन डॉलर से भी अधिक आया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण दर्शाता है-1.2 बिलियन दैनिक खर्च, ऑप्रेशन खर्च 15.2 बिलियन, संपत्ति का नुकसान 11.9 बिलियन, युद्धक हथियार 41.2 बिलियन, इसराईल को भुगतान 2.9 बिलियन और इसके अलावा पेंटागन ने 100 बिलियन डॉलर की और मांग कर रखी है।

अंधी खाई : पिछले 16 महीनों के शासनकाल में ट्रम्प अमरीकी लोगों और विशेष रूप से युवाओं की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते दिख रहे। इसके विपरीत, वह लगातार निरंकुश, चिड़चिड़े, बहके-बहके और धमकियों से भरे बयानों से लोगों को आतंकित करने वाले बनते जा रहे हैं। ईरान युद्ध के झटकों, आईस एजेंटों को विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने भेजने, ईसा मसीह की नकल करने, पोप लियो और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सत्ता के नशे और अर्ध-पागलपन के अधीन बेइज्जत करने जैसी कार्रवाइयों के कारण उनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन घटती चली जा रही है।

दिसम्बर 2025 में हार्वर्ड यूथ पोल सर्वे के अनुसार, 18 से 29 साल के केवल 13 प्रतिशत युवा अमरीकी समझते हैं कि देश सही दिशा में चल रहा है, जबकि 57 प्रतिशत इसे गलत दिशा की ओर बढ़ता देख रहे हैं। केवल 30 प्रतिशत अमरीकी मानते हैं कि उनकी स्थिति उनके माता-पिता से बेहतर है। आज के अमरीका में महंगाई उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन के काल से 3.3 प्रतिशत अधिक होने से उनके कार्यकाल में हाहाकार भी मची है।

शैक्षणिक क्षेत्र : फीस में वृद्धि, विशेष रूप से निजी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में, आम परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना दूभर कर रही है। ट्रम्प प्रशासन ने प्रदर्शनों के विरोध में बदले की कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्रों की सहायता राशि में कटौती कर दी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य क्षेत्र में 'डिग ब्यूटीफुल बिल' के तहत ओबामाकेयर सबसिडी बंद करने से एक करोड़ अमरीकी स्वास्थ्य बीमा से वंचित हो चुके हैं। ट्रम्प द्वारा लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराने के वादे पूरे नहीं हो सके हैं। 82 हजार फैक्ट्री नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कम वेतन पर रोजगार मिलने के कारण अमरीकी सुपरपावर का जनाजा निकल रहा है। ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि ने बाकी वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि ने जनता की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। ए.आई. के व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में शामिल होने के कारण युवा महसूस करते हैं कि यह उनके भविष्य और रोजगार पर बुरा असर डालेगी।

शोधकर्त्ता रेचल जनफाज के अनुसार, युवा ट्रम्प प्रशासन से बुरी तरह निराश होकर इससे दूर जा रहे हैं। नवम्बर 2026 में मध्यावधि चुनावों में ट्रम्प की नीतियों के कारण रिपब्लिकन को हार का सामना करना पड़ सकता है। यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में डैमोक्रेट्स को बहुमत हासिल हो गया, तो निश्चित रूप से ट्रम्प प्रशासन के साथ टकराव इस कदर बढ़ जाएगा कि उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, जिससे देश की विकास गति, व्यापार और जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डैमोक्रेटिक बहुल कांग्रेस उनकी मनमानी और तानाशाहीपूर्ण नीतियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विवश हो जाए।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अर्थात्- अमोघ वीर्य के कीटाणु साधारण वीर्यगत कीटाणुवों की तरह मृदु= लतोफ नहीं रहते जो कि हवा के एक झोंके से मर जाएं बल्कि वे इसके विपरीत नियमानुकूल आहार मिलने की दशा में गर्भस्थ बालक की भाँति परिपुष्ट होते होते सर्वाङ्गपूर्ण मनुष्य बन सकने की शक्ति रक्षा करते हैं।

जिस तरह आम्र फल को पेड़ पर लगे रहने की हालत में तो प्रकृति देवी स्वयं नियमानुकूल पका कर रसीला बनाती है, परन्तु मनुष्य उसे कच्चा ही तोड़ कर घास फूंस की पाल में दबा कर बनाबटी उष्णता से भी पका लेते हैं, अथवा मुर्गी के अण्डे को आजकल बिजली के यन्त्र में रख कर नकली ताप से भी सेलिया जाता है।

ठीक इसी तरह हमारे पूर्वज अमोघ वीर्य के कीटाणु को गर्भाशय की भाँति किसी खास स्थान में सुरक्षित रख कर और उसे पुष्ट करने के लिये उचित उपचार करते हुए पूरा मनुष्य बना सकने की योग्यता रखते थे।

तदनुसार ऋषियों ने प्रथम सद्योमृत वेन के जघनार्ध भाग का औपरेशन किया, जिसमें से एक जीवित वीर्य-किटाणु प्राप्त हुवा, परन्तु वह बेन के दुराचारों के प्रभाव से दूषितप्राय था, अतः उससे उसी प्रकार की पापप्रधान सन्तति के होने का ऋषियों ने अनुमान किया।

पश्चात् उसकी भुजाओं के मथने किंवा पर्यन्त्रेषण करने से उसमें से दो कीटाणु उपलब्ध हुए, जो तीनों ही ऋषियों की वैज्ञानिक रीति से परिपुष्ट किए जाने पर क्रमशः निषाद, पृथु और अचिः नाम से विख्यात हुये।

यही इस आख्यान का मूल रहस्य है। हमारे महाशयों की इतने ऊंचे विज्ञान तक पहुंच कहाँ है, वे तो सिर्फ चेमेंगोइयाँ ही करना जानते हैं।

क्रमशः ...

वीर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी थे। वे विश्वभर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार थे। उनका जीवन बहुआयामी था। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं।

वीर सावरकर का जन्म नासिक के भगूर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे, तब ही उनकी माता का देहांत हो गया था। वे बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। उन्होंने शिवाजी हाईस्कूल, नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की।

आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसायटी बनाई थी, जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1905 के बंग-भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पुणे में फर्ग्युसन कॉलेज में पढ़ने के दौरान वे राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत ओजस्वी भाषण देकर सबको प्रभावित कर देते थे। उन्हें तिलक की अनुशंसा पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोसियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे।

वे रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। मदनलाल धींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस-1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया।

वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल में रहे। उन्होंने जेल में हिन्दुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे दादर, मुंबई में रहे।

उन्होंने 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधीजी और सावरकर का नजरिया अलग-अलग था। वे दुनिया के पहले ऐसे कवि थे, जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10 हजार पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा।

उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान प्रशंसनीय और सराहनीय है।

आखिर क्या है अब्राहम अकॉर्ड का असली मतलब?

अभिनय आकाश

ईरान के साथ अभी डील साइन नहीं हुई है और ट्रंप की नजर दूसरी बड़ी डील पर पड़ गई है। ईरान जंग निपटाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा समझौता करने की कोशिश में लग गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 ट्रंप का टारगेट है कि जंग खत्म होने के बाद खाड़ी देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले यानी मोटा-मोटी इजराइल को मान्यता दे दे। इसके लिए लगातार सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बीते वीकेंड ट्रंप ने खाड़ी देशों से इसी मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कई खाड़ी नेताओं को फोन किया और कहा कि जिन देशों के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है उन्हें अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाना चाहिए। 23 मई को हुई इस बातचीत में सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्किए, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल थे। अमेरिकी मीडिया एक्सियस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप का यह प्रपोजल इतना अचानक आया कि उनकी बात सुनकर फोन पर मौजूद खाड़ी देशों के नेता चुप रह गए। इस पर ट्रंप ने मजाकिया लहजे में यह भी पूछा क्या वो अभी भी कॉल पर मौजूद हैं या नहीं। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि इसके बाद वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अगली कॉल पर खाड़ी देशों के नेताओं के साथ इजरायली प्रधानमंत्री भी जुड़ सकेंगे।

रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप का मेन फोकस सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सुधारने पर है। इजराइल हमास जंग शुरू होने से पहले तक इसकी संभावना भी बनती दिख रही थी। लेकिन फिर जंग छड़ने के बाद सऊदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पिछले साल नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। जिसकी वजह से दोनों नेताओं में गहमागहमी भी हो गई थी। उधर ईरान युद्ध और यूएई

से बढ़ते तनाव के बाद सऊदी अरब अब इजराइल की सरकार को लेकर ज्यादा सख्त हो गया है। सऊदी का कहना है कि इजराइल से रिश्ते सामान्य तभी होंगे जब वो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के लिए पक्का और तय समय वाला प्लान माने। लेकिन इजराइल की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुश्किलें सिर्फ सऊदी अरब के सामने नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दे। फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान की जनता के लिए बेहद सेंसिटिव इशू है। ऐसे में फिलिस्तीन पर कोई साफ रुख लिए बिना इजराइल को आधिकारिक मान्यता देना पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर चिंगारी लगाने जैसा हो सकता है।

अब्राहम अकॉर्ड क्या है?- यह भी जान लेते हैं। यह वह समझौते हैं जिन्हें ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका की मध्यस्था से शुरू किया गया था। इनके तहत इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य किए गए। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन सबसे पहले इसमें शामिल हुए थे। बाद में सूडान, मोरक्को और हाल में कजाकिस्तान भी जुड़ा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कोशिश किया है तो कम से कम इन देशों को एक साथ एक्स पर साइन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक दो देश मना भी कर दें तो भी चलेगा। इसी बीच हालात अब भी बेहद तनाव से भरे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर लागू है। लेकिन जमीन पर तनाव खत्म नहीं हुआ है। ईरान अभी भी हॉर्मोज स्टेट से ज्यादातर जहाजों की आवाजाही रोक रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जैसी सख्ती बढ़ा रखी है। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर शुरू होने के बाद भी छोटी-मोटी झड़पें होती रही हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ऐसी घटनाओं को वह सीज फायर टूटना नहीं मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते पहले अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में था।

अब्राहम समझौते से जुड़े वर्तमान देशों में शामिल हैं- इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान।

डोनाल्ड ट्रंप की यह नई कोशिश अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है, ताकि इलाके में जारी तनाव और लड़ाई को कम किया जा सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है! यह समझौता या तो सबके लिए बहुत शानदार होगा, या फिर होगा ही नहीं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर बात नहीं बनी, तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी, और इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक होगी। ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ समझौता होते ही सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को तुरंत अब्राहम समझौते (इजराइल के साथ दोस्ती के ऐतिहासिक समझौते) में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरे मुस्लिम देशों को भी इससे जुड़ना चाहिए। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि आगे चलकर खुद ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने जिन बड़े नेताओं से बात की है, वे सब चाहते हैं कि जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी हो, ईरान भी इस समझौते का हिस्सा बने। यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कई देशों के बड़े नेताओं से बात की है। इनमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति, कतर के अमीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति सिसी, जॉर्डन के राजा और बहरीन के राजा शामिल हैं। इसे इस पूरे इलाके के इतिहास का सबसे बड़ा और जरूरी समझौता बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को इस पर काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों के नाम लिए थे, उनमें से पाकिस्तान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सार्वजनिक रूप से (सबके सामने) इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने वहां के एक टीवी चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद (पाकिस्तान) ऐसे किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करेगा, जो इजराइल को लेकर देश की बुनियादी विचारधारा के खिलाफ हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधारा के खिलाफ जाता हो। इजराइल के साथ बातचीत पर भरोसा जताने को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता? उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी नीति को दोहराते हुए कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि यह हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। आसिफ ने पाकिस्तान के पासपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं, जिसके पासपोर्ट पर इजराइल का नाम तक नहीं लिखा है (यानी वहां के नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं है)।

पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वह इज़राइल को मान्यता देता है। उसका कहना है कि राजनयिक संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं जब 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य का गठन हो जाए और पूर्वी यरुशलम उसकी राजधानी हो। 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से यह मुद्दा इस्लामाबाद के लिए और भी संवेदनशील हो गया है। जहां संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे करीबी खाड़ी सहयोगी इज़राइल के साथ सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता और फ़िलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन के कारण इससे दूर रहा।

आज का इतिहास

1838 ब्रौलीओ कैरिलो को कोस्टा रिका राज्य के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई, इस प्रकार उन्होंने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की।

1889 आंद्रे मिशेलिन और एडुअर्ड ने मिशेलिन टायर कंपनी को एक में मिलाया।

1892 कैलाफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा सहायता प्राप्त, संरक्षणवादी जॉन मुइरफॉन्ड ने सैन फ्रांसिस्को में पर्यावरण संगठन सिएरा क्लब में प्रवेश किया।

1895 माधवराव खंडेराव बागल का जन्म हुआ था। माधवराव खांडराव बागल को भाई माधवराव बागल भी कहा जाता था, वे कोल्हापुर के एक लेखक, कलाकार, पत्रकार, समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, संत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे।

1923 अमेरिकी बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई।

1937 नेविले चेम्बरलिन के उदय का समापन हुआ, जब वह चुंबन हाथ के लिए बकिंघम पैलेस के लिए बुलाया और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया गया था।

1940 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बेल्जियम ने जर्मनी से हार मानी।

1952 यूनान में महिलाओं को मताधिकार मिला।

1959 अमेरिका ने दो बंदरों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा।

1960 सेल बायोलॉजी के लिए अमेरिकन सोसायटी का आयोजन किया गया।

1961 मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई।

1963 बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान से करीब 22 हजार लोगों की मौत।

1971 सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान मार्स-3 का प्रक्षेपण किया।

1975 सोलह पश्चिम अफ्रीकी देशों ने लागोस की संधि पर हस्ताक्षर किए, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय को प्रोत्साहन आर्थिक एकीकरण की स्थापना की।

1977 अमेरिका के केंटकी के साउथगेट में बेवर्ली हिल्स सपर क्लब में आग लगने से 165 संरक्षक मारे गए।

1987 वेस्ट जर्मन एविएटर माथियास रस्ट ने अपने सेसना 172 से उड़ान भरी, माना जाता है कि यह सोवियत वायु रक्षा प्रणाली के माध्यम से उड़ान भरता है और मास्को के रेडस्करे में उतरा है।

1998 पाकिस्तान ने पहला परमाणु परिक्षण किया।

2004 इराक़ के अंतरिम प्रधानमंत्री होने के लिए इराकी गवर्निंगकैसिल द्वारा आयद अल्लावी को सर्वसम्मति से चुना गया था।

भाजपा का अश्वमेध यज्ञ! अगला लक्ष्य! दक्षिण?

राजीव खंडेलवाल

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में यदि किसी एक दल की रणनीतिक निरंतरता, संगठनात्मक अनुशासन और विस्तारवादी राजनीतिक भूख सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा की उल्लेखनीय सफलता को एक प्रकार की वैचारिक घर-वापसी भी कहा जा रहा है। हालांकि यह प्रश्न अभी भी राजनीतिक गलियारों में चाय की प्याली में तूफान बना हुआ है कि बंगाल में आया परिवर्तन वास्तव में बदला नहीं बदलाव था, या बदले की भावना से उपजा बदलाव? राजनीति में अक्सर दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, इसलिए विपक्ष इस परिणाम को सहजता से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आत्मविश्वास बैरकपुर की अंतिम चुनावी सभा में स्पष्ट रूप से व्यक्ति उनके इस कथन के साथ हुआ— 4 मई के बाद बंगाल में भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में आना ही है।

यद्यपि कांग्रेस-विहीन भारत का लक्ष्य अभी पूर्णत: साकार नहीं हुआ, किंतु भाजपा का वन नेशन, वन पार्टी की दिशा में बढ़ना अब केवल विपक्ष का आरोप नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने लोहे को गर्म देखकर चोट करना सीख लिया है।

2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सत्ता में आने के बावजूद भाजपा को अपेक्षित बहुमत न मिलना पार्टी के लिए आसमान से गिरकर खजूर में अटकने जैसा क्षण अवश्य था, किंतु यही झटका भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आत्ममंथन का अवसर बन गया। गृह मंत्री अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट शैली, बूथ स्तर तक की रणनीति और संघ परिवार के जमीनी नेटवर्क ने भाजपा को पुन: राजनीतिक पटरी पर लौटा दिया। भाजपा ने सिद्ध किया कि वह हार को ठोकर नहीं, बल्कि सीढ़ी बनाना जानती है।

लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिस प्रकार बाउंस बैक किया, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। चार राज्यों के आसीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक एमके स्टालिन और ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में कहा जाता है— जो सोता है, वही खोता है। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि भाजपा चुनाव को इवेंट नहीं निरंतर प्रक्रिया मानकर चलती है।

भाजपा चुनाव को पाँच साल का उत्सव नहीं, बल्कि 24×7 चलने वाली राजनीतिक

साधना मानती है। यही कारण है कि शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो जाती है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने संघर्षशील नेता की छवि बनाए रखी, किंतु भाजपा का संगठनात्मक ढाँचा और विस्तार अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। दूसरी ओर राहुल गांधी की सीमित चुनावी सक्रियता ने विपक्ष की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया।

राजनीति में एक पुरानी कहावत है— जितना पसीना अभ्यास में बहाओगे, उतना खून मैदान में नहीं बहेगा। भाजपा ने इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारा है, जबकि विपक्ष कई बार नौ दिन चले अढ़ाई कोस की स्थिति में दिखाई दिया।

सामान्यत: लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों के विरुद्ध एंटी-इनकंबेंसी पैदा होती है, किंतु भाजपा ने गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस धारणा को सफलता पूर्वक चुनौती दी। यह केवल चुनावी प्रबंधन नहीं, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल और जमीनी संपर्क का परिणाम है। भाजपा ने यह समझ लिया है कि राजनीति में जो दिखता है, वही बिकता है।

पश्चिम बंगाल में दो तिहाई से ज्यादा लगभग 70त्न सीटें प्राप्त कर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित उनके 22 मंत्रियों की हार भाजपा की निर्णायक जीत ही कहलाएगी। बावजूद इसके मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस के बीच लगभग 32 लाख वोटो का अंतर और लगभग उतने ही मतदाताओं के नाम सूची से गायब थे। (27 लाख मतदाता वंचित किए गए और 5 लाख जोड़े गए।) किंतु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या बिना प्रमाण यह मान लिया जाए कि सूची से बाहर हुए सभी मतदाता किसी एक दल के समर्थक थे?

भारत का लोकतंत्र गुप्त मतदान की संवैधानिक अवधारणा पर आधारित है। जब तक मतदाता स्वयं यह न बताए कि उसने किसे वोट दिया, तब तक उसकी राजनीतिक पहचान तय करना आँख मूँदकर तीर चलाने जैसा है।

उच्चतम न्यायालय की संभावित चिंता अगर जीत का अंतर बहुत कम है और बड़ी संख्या में मतदाताओं (जैसे 15%) को वोट देने अधिकार नहीं मिला, तो कोर्ट को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, को आधार बनाकर इस्तीफे से इनकार करना भी राजनीतिक बहस का विषय है। भारतीय राजनीति में यह घटना ऊँट के मुँह में जीरा नहीं, बल्कि बड़े संवैधानिक विमर्श का संकेत बन चुकी है।

यह चुनाव एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है— क्या क्षेत्रीय दल राष्ट्रवाद के मार्ग में अवरोध हैं? भाजपा के बढ़ते प्रभाव ने तथा तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्रीय दलों के संबंध में दिए गए अभियान में बयान ने गंभीर चिंतन अवश्य इस बहस को और तेज कर दिया है।

हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय या गैर-भाजपा दलों की मजबूती भारतीय लोकतंत्र की विविधता को दर्शाती है। स्पष्ट है कि भारत में एक फूल से माला नहीं बनती। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय— दोनों प्रकार की राजनीतिक शक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान है।

अंग-बंग-कलिंग (बीच में झारखंड को छोड़कर) पर विजय के बाद 30 के 72% विभाग और उत्तर प्रदेश जनसंख्या का झंडा गाड़ने के बाद भाजपा के अश्वमेध यज्ञ का अब अगला निशाना उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति करते हुए दक्षिण के शेष बचे राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर भगवा झंडा फहराना है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक उभरी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीतिक जिज्ञासा अवश्य पैदा की है। यह भाजपा विरोध की नई डिजिटल अभिव्यक्ति है या विपक्षी दलों की जमीन खिसकाने वाला नया प्रयोग — यह भी स्पष्ट नहीं है।

फिलहाल इसकी घोषित नीति भाजपा का विरोध और अघोषित नीति विपक्ष की आलोचना प्रतीत होती है। राजनीति में कई बार घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति भी बन जाती है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रयोग भाजपा के लिए चुनौती बनता है या विपक्ष के वोट बैंक में ही सेंध लगा देता है। अंतत: प्रश्न यही है कि क्या कोई दल इस अश्वमेध यज्ञ को रोक पाएगा, या विपक्ष केवल ढाक के तीन पात साबित होगा? उत्तर भविष्य के गर्भ में है।

भाजपा का विस्तार केवल चुनावी जीत का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति, संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्व की स्पष्टता और सतत राजनीतिक सक्रियता का परिणाम है। किंतु भारतीय लोकतंत्र की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी राजनीतिक अश्वमेध पूर्णत: निर्विरोध नहीं हो सकता। राजनीति में न जीत स्थायी होती है, न हार अंतिम। स्थायी यदि कुछ है, तो वह है— सकारात्मक संघर्ष, जन विश्वास और समय के साथ स्वयं को बदलने की क्षमता। अंतत: लोकतंत्र में वही दल टिकता है जो जनता की नब्ज पहचान ले। क्योंकि राजनीति में समय से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं होता।

तृणमूल कांग्रेस के दो-तिहाई सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में भारी अफरातफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। सांसद, विधायक और पार्षद या तो अपने इलाकों से दूर हैं या फिर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक कि विधायकों की मौजूदगी भी ममता बनर्जी की बैठकों और कार्यक्रमों में अपेक्षित संख्या में नहीं दिख रही है। पार्षदों के स्तर पर स्थिति और अधिक गंभीर मानी जा रही है। कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं में सामूहिक इस्तीफों की होड़ मची हुई है। कहीं एक-तिहाई से अधिक तो कहीं दो-तिहाई से भी ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। इसके चलते कई शहरी निकायों में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। माना जा रहा है कि प्रशासक नियुक्त कर अस्थायी रूप से इस संकट को संभाला जा सकता है। अगला निकाय चुनाव फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य लगातार यह बयान दे रहे हैं कि भाजपा का दरवाजा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए बंद है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि तृणमूल के दो-तिहाई से अधिक सांसद दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल सांसद स्तर पर कुछ नरमी दिखा सकता है। इसकी एक बड़ी वजह लोकसभा की संख्या गणित को माना जा रहा है। वर्तमान में भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत से कम सीटें हैं और उसे एनडीए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विशेष रूप से टीडीपी और जदयू जैसे सहयोगियों के समर्थन पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी इसके पीछे एक कारण मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में फिलहाल 29 सांसद हैं, जबकि दल में विभाजन के लिए कम से कम 20 सांसदों का समर्थन आवश्यक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस दिशा में ऑपरेशन लोटस के तहत अंदरखाने कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के पांच मुस्लिम सांसदों के साथ-साथ अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को भाजपा में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। बाकी बचे 22 सांसदों में दो पूर्व भाजपा सांसद भी शामिल हैं, जो मूल रूप से बंगाल के निवासी नहीं हैं। इन दोनों को लेकर भाजपा नेतृत्व को अंतिम निर्णय लेना है। ममता बनर्जी ने जाने-अनजाने में इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया, जब उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार को नाराज़ कर दिया। ममता बनर्जी ने लोकसभा में उनसे मुख्य सचेतक का पद वापस लेकर कल्याण बनर्जी को सौंप दिया, जबकि दोनों का रिश्ता चार दशक से भी अधिक पुराना माना जाता रहा है। भाजपा ने भी काकोली घोष दस्तीदार की नाराज़गी को राजनीतिक तौर पर भुनाने में देर नहीं की। केंद्र सरकार ने उन्हें सीआईएसएफ की वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराई है। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर यह सुरक्षा दी गई। इसके बाद इन्होंने आई-पैक पर निशाना साधते हुए बारासात संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। बहरहाल, काकोली घोष दस्तीदार की नाराज़गी को अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर संभावित असंतोष और भगदड़ के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो सांसद पार्टी नेतृत्व से असहज हैं और भाजपा में संभावनाएं तलाश रहे हैं, वे काकोली घोष दस्तीदार के संपर्क में बताए जा रहे हैं।

उत्तराखंड, गुजरात के बाद असम में भी यूसीसी

नीरज कुमार दुबे

राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात इस दिशा में पहल कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा लंबे समय से समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख वैचारिक संकल्प के रूप में प्रस्तुत करती रही है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब समान नागरिक संहिता को लागू करना भाजपा के तीसरे बड़े वैचारिक वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत किया। राज्य के मंत्री अतुल बोरा ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा और मतदान विधानसभा सत्र के अंतिम दिन होने की संभावना है। हम आपको याद दिला दें कि असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद 13 मई को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले सभी आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मान्यताएं भी इससे प्रभावित नहीं होंगी। असम सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य न्यूनतम विवाह आयु तय करना, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिलाना, बहुविवाह पर रोक लगाना, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा साथ रहने वाले संबंधों को कानूनी मान्यता देना है।

इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में आदिवासी समाज को महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता के दायरे से सभी आदिवासी समुदायों को बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से आदिवासियों के भूमि, जंगल और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी। अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज अपनी जमीन और जंगल का वास्तविक मालिक है और कोई भी उनके अधिकारों पर कब्जा नहीं कर सकता।

केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर अक्सर आदिवासी समाज के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। कई राजनीतिक दल और संगठन यह प्रचार करते रहे हैं कि इस कानून से आदिवासियों की परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होंगी। लेकिन केंद्र और भाजपा शासित राज्य लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बंगाल चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यह बयान बताता है कि भाजपा इस मुद्दे को केवल वैचारिक बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि राज्यों में चरणबद्ध तरीके से यूसीसी को लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है।

साथ ही समान नागरिक संहिता को लेकर उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने भी इस बहस को नई दिशा दी है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि उत्तराधिकार कानूनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान समान नागरिक संहिता ही है। न्यायालय ने माना कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और सुधार के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि इस विषय को विधायिका के विवेक पर छोड़ना बेहतर होगा ताकि समान नागरिक संहिता जैसा कानून बनाया जा सके। दरअसल समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून लागू करना है। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जिससे कई बार महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार प्रभावित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 भी राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है।

बहरहाल, यूसीसी संबंधी असम सरकार का निर्णय देशहित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, विवाह और तलाक से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी तथा बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही आदिवासी समुदायों को दायरे से बाहर रखकर सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक सुधार का प्रमुख विषय बनने वाला है।

ईरान पर अमरीकी दबाव के पीछे छिपा तेल का रहस्य

रेबेका फेंग और जॉर्जी कंचेव

अमरीका सरकार, तेल व्यापारी और निजी विश्लेषक इस बात पर बंटे हुए हैं कि तेहरान के पास कच्चा तेल छिपाने के लिए जगह खत्म होने से पहले कितना समय बचा है। यह अमरीका-ईरान युद्ध के केंद्र में एक करोड़ों बैरल का रहस्य बन गया है-तेहरान के पास उस तेल को भंडारित करने के लिए जगह खत्म होने से पहले कितना समय है जिसे वह अब निर्यात नहीं कर सकता? इस प्रश्न का उत्तर संघर्ष के परिणाम को निर्धारित करने में सहायक हो सकता है। फारस की खाड़ी के अंदर हो रहे ईरान के तेल रिसाव के चलते तेहरान को फंसे हुए तेल के बैरल तेजी से भर रहे भंडारण टैंकों में और पास में मौजूद जहाजों के बेड़े में पंप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमरीकी अधिकारियों को उम्मीद है कि जब ईरान के पास तेल छिपाने के स्थान खत्म हो जाएंगे, तो उसे अपने तेल क्षेत्रों को बंद करने के लिए एक महंगा और उच्च जोखिम वाला कदम उठाना पड़ेगा, जिससे तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और व्यापक संघर्ष पर बातचीत में झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

हालांकि, अमरीका सरकार, तेल व्यापारी और निजी विश्लेषक इस बात पर बंटे हुए हैं कि तेहरान के पास 'टैंक टॉप' तक पहुंचने में वास्तव में कितना समय है, जो भंडारण समाप्त होने के लिए उद्योग की शब्दावली है.ईरान के तटवर्ती क्षेत्रों का अनुमान क्षमता 57 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक व्यापक रूप से भिन्न है। इसका अर्थ है कि तेहरान कुछ ही दिनों में संकट में फंस सकता है, या हफ्तों तक स्थिति को संभाल सकता है। कुओं को धीरे-धीरे बंद करना और निष्क्रिय जहाजों को तैरते हुए भंडारण के रूप में उपयोग करना ईरान को स्थिति को और अधिक खींचने में मदद कर रहा है। युद्धविराम के दौरान दोनों पक्षों के बीच आर्थिक खींचतान का दौर चल रहा है। होर्मुज जल डमरूमध्य के बंद होने से तेहरान को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक तेल निर्यात से होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कमी और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण पश्चिमी देशों की सहनशीलता की भी परीक्षा हो रही है।

पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान सरकार राजस्व के लिए तेल की बिक्री पर अत्यधिक निर्भर है और कुल

निर्यात राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा तेल तथा तेल उत्पादों की बिक्री से आता है। इस नाकाबंदी के कारण ईरान का समुद्री निर्यात, जिसका अधिकांश हिस्सा चीन को जाता है, युद्ध-पूर्व औसत 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर लगभग शून्य हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरानियों को बढ़ती कीमतों और आर्थिक कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि देश युद्ध की लागतों को वहन कर रहा है, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे को नुकसान और तेल निर्यात में बढ़ती कठिनाई शामिल है। ईरान के भंडारण पर लगाई गई सीमाएं अभी तक तेहरान को तत्काल राजनीतिक आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर पाई हैं लेकिन ये सीमाएं इस बात की परीक्षा ले रही हैं कि ईरान चरम परिस्थितियों में कितने समय तक टिक सकता है।

यूरेशिया ग्रुप कंसल्टिंग फर्म में ईरान पर ध्यान केंद्रित करने वाले वरिष्ठ विश्लेषक ब्रू के अनुसार, ''वे 'न शांति, न युद्ध' की इस यथास्थिति को समाप्त करना चाहते हैं और अमरीका के साथ टकराव का समाधान चाहते हैं।''

'मैक्केरी' के वैश्विक ऊर्जा रणनीतिकार विकास द्विवेदी का अनुमान है कि युद्ध-पूर्व ईरान के तेल बिक्री राजस्व का उसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान था। ''इसलिए कुल नुकसान भी उनके जी.डी.पी. के लिए विनाशकारी झटका नहीं है लेकिन यह उनके सरकारी राजस्व और सैन्य खर्च के बजट पर बहुत बड़ा असर डालेगा।''

अप्रैल के अंत में, अमरीका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि ईरान के पास तेल पाइपलाइनों के अवरुद्ध होने से विस्फोट होने के खतरे से पहले लगभग 3 दिन का समय है। पिछले सप्ताह, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान का तेल भंडार भर गया है और तेहरान को तेल उत्पादन बंद करना होगा। एस. एंड पी. ग्लोबल एनर्जी का अनुमान है कि तटवर्ती कच्चे तेल का भंडार लगभग 57 प्रतिशत भरा हुआ है, जो साल के इस समय के ऐतिहासिक स्तर से कम है। जे.पी. मॉर्गन का अनुमान है कि यह संख्या 64 प्रतिशत है, यानी भंडार पूरी तरह भरने से पहले लगभग 3 सप्ताह के निर्यात के बराबर तेल बचा है। दूसरी ओर, डाटा प्रदाता केप्लर का अनुमान है कि तटवर्ती टैंक 90 प्रतिशत भरे हुए हैं। अनुमानों में व्यापक भिन्नता ईरान की तेल प्रणाली की अपारदर्शिता को दर्शाती है। विश्लेषक तैरते हुए टैंकों की छतों के उतार-चढ़ाव को मापने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हैं और उनकी छाया के आकार से उनकी क्षमता का अनुमान लगाते हैं। हालांकि, स्थिर छत वाले टैंक, निजी भंडारण स्थल और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का आकलन करना अधिक कठिन है। कुछ अनुमानों में घरेलू रिफाइनरियों में भंडारण शामिल नहीं है।

अमरीकी नाकाबंदी को तोडने में असमर्थ तेहरान फंसे हुए टैंकरों में कच्चा तेल भर रहा है और उन्हें अस्थायी तैरते भंडारण स्थलों के रूप में उपयोग कर रहा है। इस बीच, तेहरान कुओं से तेल उत्पादन को धीरे-धीरे कम कर रहा है। एक साथ पूरी तरह बंद करने की बजाय, वह चरणबद्ध तरीके से उत्पादन कम कर रहा है, ताकि तेल क्षेत्रों को बंद करने और बाद में उन्हें फिर से शुरू करने में हफ्तों या महीनों का खर्च उठाने जैसे महंगे कदम से बचा जा सके। ईरान रिफाइनरी उत्पादन में भी सक्रिय रूप से वृद्धि कर रहा है। यह रेल और ट्रकों के माध्यम से, सड़क मार्ग से तथा कैस्पियन सागर के रास्ते प्रतिदिन लगभग 2,00,000 बैरल का निर्यात करने में सक्षम है। यह पहली बार नहीं है जब तेहरान को वाशिंगटन से बचने के लिए अपने ऊर्जा क्षेत्र को निष्क्रिय करना पड़ा है। इससे इस बार अमरीकी दबाव अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। 2019 में ट्रम्प द्वारा तेहरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद 3 साल से अधिक समय तक ईरानी तेल निर्यात में भारी गिरावट आई। उत्पादन भी प्रभावित हुआ और घटकर 20 लाख बैरल प्रति दिन से नीचे आ गया। हालांकि, 2022 में उत्पादन में फिर से तेजी आई और इस साल की शुरुआत में यह कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन पर सस्पेंस बरकरार

हिमांशु सिंह चंदेल

कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चल रही नेतृत्व की खींचतान अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लंबी बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद पार्टी ने साफ तौर पर किसी नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया, लेकिन अंदरखाने में चर्चा तेज बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बैठक में केवल राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रही सत्ता की लड़ाई पर भी शीर्ष नेतृत्व ने अलग-अलग बातचीत की। माना जा रहा है कि अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर अंतिम फैसला कर सकती है। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, शिवकुमार खेमे का दावा है कि 2023 विधानसभा चुनाव के समय उन्हें ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। अब उनके समर्थक उसी वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसमें उन्हें राज्यसभा भेजने का विकल्प शामिल बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है और इसी उम्र के मुद्दे को भी नेतृत्व परिवर्तन की बहस में उठाया जा रहा है। कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस तीन सीटें जीत सकती है, जबकि एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खरगे को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताया जा रहा है। पार्टी एक महिला या ओबीसी चेहरे को भी मौका दे सकती है। साथ ही विधान परिषद की सात सीटों पर भी चर्चा हुई, जहां कांग्रेस को चार सीटें मिलने की संभावना है। दिल्ली पहुंचते समय दोनों नेताओं के साथ उनके समर्थक विधायक भी मौजूद थे। इससे साफ संकेत मिला कि दोनों खेमे अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। बैठक के बाद सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों के साथ अलग बैठक भी की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले किसी बड़े विवाद से बचना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से किसी भी बदलाव की बात से इनकार कर रहा है। लेकिन अंदरूनी हलचल यह संकेत दे रही है कि राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आ सकता है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की बातें केवल अटकलें हैं। उन्होंने कहा कि बैठक पूरी तरह राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर केंद्रित रही। उनके साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। सिद्धारमैया ने भी साफ कहा कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। वहीं कैबिनेट फेरबदल के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में अलग-अलग बैठकों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन का मन बना चुका है। पार्टी शिवकुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाना चाहती है। राहुल गांधी के साथ सिद्धरमैया की 35 मिनट अकेले में बातचीत हुई। इसके बाद, सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार सुबह मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

दिशा पाटनी ने 11 साल लम्बे करियर में 12 फिल्में की एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद

मुझे हमेशा से एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद रहा है। बॉलीवुड में मैंने जो अनुभव हासिल किया, अब उसे दुनिया भर में दिखाने का मौका मिला है। यह मेरे करियर का बेहद खास पल है। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद अब दिशा पाटनी भी हॉलीवुड के माध्यम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है । उसकी पहली इंटरनैशनल फिल्म 'द पोर्टल ऑफ फोर्स' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

ट्रेलर में वह एक्शन करती नजर आ रही है फिल्म एक काल्पनिक और रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। यह 'स्टेटिगार्ड्स वर्सेज होलीगार्ड्स' नाम की नई फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है। इस कहानी को लाडो ओखोटनिकोव ने तैयार किया है ।

एक और खास बात फिल्म की स्टार कास्ट है । दिशा के साथ फिल्म में हॉलीवुड के कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। इनमें केविन स्पेसी, डॉल्फ लुंडग्रेन और टायरेस गिब्सन जैसे नाम शामिल हैं।

दिशा ने इस फिल्म को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं लंबे समय से इस ट्रेलर के रिलीज होने का इंतजार कर रही थी। पहली इंटरनैशनल फिल्म में काम करना मेरे लिए एक साथ रोमांचक और डराने वाला अनुभव रहा। अलग-अलग देशों के कलाकारों के साथ काम करते हुए मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। इन कलाकारों के साथ काम करना ही अपने आप में एक सीख थी

दिशा ने यह भी बताया कि भारतीय सिनेमा में मिले अनुभवों और सीखों को एक इंटरनैशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने पर उसे गर्व महसूस होता है । दिशा ने कहा, ₹मुझे हमेशा से एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद रहा है। बॉलीवुड में मैंने जो अनुभव हासिल किया, अब उसे दुनिया भर में दिखाने का मौका मिला है ।

यह मेरे करियर का बेहद खास पल है।

उसका मानना है कि कहानी सुनाना एक 'यूनिवर्सल आर्ट' (वैश्विक कला) है जो लोगों को संस्कृतियों और सीमाओं के पार जोड़ती है ।

उसने कहा, "आपको एहसास होता है कि कहानी कहने का तरीका भाषा और भूगोल से परे है - स्क्रीन पर ईमानदारी 'यूनिवर्सल' है। मुझे हमेशा से एक्शन पसंद रहा है, और जो मैंने अपने देश में सीखा है उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मजबूती देता है । ₹ फिल्म में दिशा का किरदार

फिल्म में दो प्राचीन शक्तियों के बीच संघर्ष दिखाया गया है। एक पक्ष दुनिया में नियम और संतुलन बनाए रखने की बात करता है, जबकि दूसरा पक्ष अलग सोच और अलग रास्ते पर चलता है।

इसी संघर्ष के बीच दिशा का किरदार जैसिका सामने आता है, जो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। फिल्म में जैसिका को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है, जिसका संबंध दोनों विरोधी पक्षों से है। वह दोनों गुटों के लीडर की बेटी है।

यही वजह है कि उसे दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल माना जा रहा है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दुनिया का भविष्य उसी के फैसले पर निर्भर होता है।

ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं, जहां जैसिका अपनी शक्तियों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं होती, बल्कि खुद को पहचानने और सही रास्ता चुनने की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है।

ट्रेलर में दिशा का एक्शन अवतार सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वह कई खतरनाक लड़ाई वाले सीन्स में नजर आती है । कभी तलवारों के साथ, तो कभी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिशा दिखाई देती है ।

दिशा पाटनी : 11 साल लम्बे करियर में 12 फिल्में

दिशा सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी खूबसूरती की वजह से छाई रहती है। अपने फिल्मी करियर के दौरान उसने कुछ ही हिट फिल्में हैं। हालांकि, उसे ग्लैमरस अंदाज के लिए ज्यादा जाना जाता है।

लगभग 11 वर्षों के फिल्मी करियर में उसने 12 फिल्में ही की हैं। दिशा ने अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत साल 2015 में तेलुगु फिल्म 'लोफर' से की थी ।

इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ द्वारा किया गया था।

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई जिससे शुरुआती दौर में ही उसे खराब दिनों का सामना करना पड़ा। साल 2016 में वह फिल्म 'एम एस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' में नजर आई। यह उसकी दूसरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत यह फिल्म भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के संघर्षों पर बनी थी।

इस फिल्म में दिशा द्वारा निभाई गई प्रियंका झा की भूमिका को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म सुपरहिट रही और दिशा को कई अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया जिसमें उसे आईफा का बैस्ट फीमेल डेब्यू खिताब भी शामिल था।

इसके बाद वह जैकी चैन की चीनी फिल्म 'कुंग फू योगा' में नजर आई। फिर उसने 'बागी 2', 'भारत', 'मलंग', 'बागी 3', 'राधे','एक विलेन रिटर्न्स', 'योद्धा', 'कंगुवा' जैसी फिल्मों में काम किया। पिछली बार वह साल 2024 में फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में दिखी थी।

अगली फिल्में

दिशा की अगली फिल्मों की बात करें तो उसे 'द पोर्टल ऑफ फोर्स' के अलावा अक्षय कुमार के लीड रोल वाली मल्टीस्टारर फिल्म 'वैलकम टू 'द जंगल' और 'आवारापन 2' में देखा जाएगा।

'आवारापन 2' में दिशा के साथ इमरान हाशमी है। विशेष फिल्म्स और नितिन कक्कर द्वारा निर्देशित यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

विवादों के बीच रिलीज हुआ 'है जवानी तो इश्क होना है' का 'चुनरी चुनरी' गाना

यूजर्स को याद आए सलमान खान

वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है'

अपनी रिलीज से पहले ही चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म में गानों को लेकर एक विवाद भी चल रहा है। इसमें एक गाना सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' का 'चुनरी चुनरी' भी है। आज इस गाने का रीमेक वर्जन रिलीज किया गया है, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आ रही हैं। इस गाने के रिलीज होने के बाद अब इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

हमारी भावनाओं से मत खेलो

90 के दशक का पॉपुलर गाना 'चुनरी चुनरी' का रीमेक वर्जन वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' से रिलीज हो गया है। हालांकि, इस गाने ने दर्शकों को निराश किया है। यही वजह है कि गाना सुनने के बाद कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर निगेटिव रिएक्शन दिए हैं।

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'इतने अच्छे गाने की ऐसी तैसी कर दी।' एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सुष्मिता और सलमान की जोड़ी बेहद खूबसूरत थी, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता।' एक अन्य ने लिखा, 'सलमान और सुष्मिता की केमिस्ट्री की बहुत याद आती है।'

डेविड धवन द्वारा निर्देशित 'है जवानी तो इश्क होना है' के इस गाने और टाइटल ट्रैक को लेकर पहले से ही विवाद जारी है। फिल्म निर्माता वाशु भगनानी ने इसको लेकर टिप्स और रमेश तौरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

इन आरोपों के बीच मेकर्स ने अब आज ये गाना रिलीज कर दिया है। बात करें 'है जवानी तो इश्क होना है' की, तो ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी।

अनन्या पांडे के बचाव में आईं कोरियोग्राफर, भरतनाट्यम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं थीं अभिनेत्री

फिल्म 'चांद मेरा दिल' की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की फिल्म में भरतनाट्यम करने की कोशिश करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। इस मामले पर अनन्या पांडे और फिल्म के मेकर्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मगर गाने की असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्ट्रेस की कोशिशों और कुछ ही दिनों में भरतनाट्यम सीखने के उनके प्रयास का बचाव किया है।

असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने किया बचाव

फिल्म की एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर अनन्या कुरुप ने अनन्या पांडे के साथ सेट के पीछे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। जब एक्ट्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ा, तो कुरुप ने उस पोस्ट पर कमेंट किया। उन्होंने एक्ट्रेस का बचाव किया और कहा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी क्लासिकल आर्ट फॉर्म को

आजमाने के लिए हिम्मत और लगन की जरूरत होती है। उन्होंने आगे लिखा 'भरतनाट्यम एक ऐसी चीज है जिसके लिए डांसर वर्षों तक ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वे इसकी अदा, हाव-भाव और तकनीक में माहिर हो सकें। अनन्या ने बहुत कम समय में सच्ची मेहनत और कोशिश की है। इसकी तारीफ होनी चाहिए।' कुरुप ने अपने नोट के आखिर में लोगों से अपील की कि वे उन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं जो खुद को चुनौती देकर अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं, न कि उन्हें नीचा दिखाएं।

क्या है डांस के पीछे की कहानी?

'चांद मेरा दिल' में, अनन्या के किरदार चांदनी को भरतनाट्यम फ्यूजन डांस के साथ पेश किया गया है। फिल्म में यह सीन इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन होता है।

लक्ष्य का किरदार आरव शुरू में इस बात से अनजान होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब चांदनी अपना भरतनाट्यम शुरू करती है, तो आरव उसे जज करता है। लेकिन जैसे ही वह मॉडर्न बीट पर थिरकना शुरू करती है, आरव उससे प्रभावित हो जाता है। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है।

कब रिलीज हुई फिल्म?

विवेक सोनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' दो स्टूडेंट्स की कहानी है। यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 'चांद मेरा दिल' में परेश पाहुजा, मनीष चौधरी, इरावती हर्षे और चारू शंकर भी नजर आए हैं।

'जवान' के बाद अब सलमान की फिल्म में एक्शन का दम दिखाएंगी नयनतारा; विशेषज्ञों की निगरानी में करेंगी स्टंट

सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के अपोजिट साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा नजर आएंगी। शीर्षक फाइनल नहीं होने के चलते अस्थाई रूप से इस फिल्म को SVC59 कहा जा रहा है। फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें नयनतारा एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आएंगी।

दमदार एक्शन से हैरान करेंगी नयनतारा?

इससे पहले नयनतारा को बॉलीवुड फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान के साथ देखा गया था। 'जवान' में भी नयनतारा का एक्शन देखने को मिला। उन्होंने अपने स्टंट से दर्शकों को हैरान कर दिया था। अब चर्चा है कि सलमान खान की आगामी फिल्म में भी वे दमदार एक्शन करती दिखेंगी। इससे फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है।

एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुद करेंगी स्टंट

मेकर्स की तरफ से फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा इस फिल्म में एक मजबूत और दमदार किरदार निभाती हुई दिखेंगी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, नयनतारा एक्टर सलमान खान के साथ एक एक्शन से भरपूर रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा, वे एक्सपर्ट्स की देखरेख में अपने स्टंट खुद ही करेंगी। ऐसा लगता है कि उनका किरदार काफी दमदार और अहम होने वाला है।

मनाली में चल रही शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल मनाली में चल रही है, जहां एक महत्वपूर्ण शेड्यूल पर काम हो रहा है। एक्शन सीन्स के साथ-साथ, लीड जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री भी चर्चा का विषय बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान और नयनतारा के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। सलमान खान और नयनतारा के अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएंगे।

'खुद को 'धुरंधर' समझने लगे..'; रणवीर से नाराज फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज अध्यक्ष बीएन तिवारी

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कल (25 मई) को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कॉपरेशन नोटिस जारी कर दिया। यह कार्रवाई फरहान अख्तर की शिकायत के बाद हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रणवीर ने शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले फिल्म 'डॉन 3' से खुद को अलग कर लिया। इस वजह से मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इस पूरे विवाद पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज अध्यक्ष बी.एन तिवारी से बातचीत में रणवीर सिंह पर खुलकर हमला बोला है।

'45 करोड़ लगवाकर अब बोल रहे फिल्म नहीं करनी'

बीएन तिवारी ने दावा किया कि फिल्म पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थीं। उन्होंने कहा, 'इशू इनका सिर्फ इतना नहीं है कि शूटिंग नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि पहले पूरा काम शुरू कराया गया, प्रोडक्शन आगे बढ़ाया गया और उसके बाद करोड़ों रुपये खर्च करवा दिए गए। करीब 45 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर लग चुके हैं। अब अचानक बोलते हैं कि हमें फिल्म नहीं करनी है। अब उनको 'धुरंधर' जैसी फिल्म चाहिए। भाई, हर बार वैसी फिल्म कहां से आएगी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2023 से चल रहा है। बीएन तिवारी का दावा है कि रणवीर के हिसाब से स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए।

23-24 लोकेशन बुक की गईं, मेंबर्स के टिकट खरीदे गए।

प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां पूरी की गईं।

इतने बड़े प्रोजेक्ट में 45 करोड़ कोई छोटा पैसा नहीं होता।

तीन साल का समय लग गया इस पूरी प्रक्रिया में।

'साइलेंट कैसे चलेगा भाई?'

तिवारी ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस लगातार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रणवीर या उनकी टीम की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। अभिनेता की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर करते हुए तिवारी ने कहा, 'अगर 45 करोड़ नहीं भी लगे होंगे तो 40 करोड़ तो जरूर लगे होंगे। उनका ऑडिट हुआ होगा, रिपोर्ट होगी और वो दिखाने के लिए भी तैयार हैं। वो बैठकर बात करने को तैयार हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि रणवीर सामने बैठें और बात करके मामला खत्म करें। लेकिन उनका रवैया ऐसा है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहते। बात नहीं करना चाहते। लगातार अवॉइड कर रहे हैं। अब साइलेंट रहकर चीजें नहीं चलतीं। साइलेंट कैसे चलेगा भाई? इंडस्ट्री में हर किसी की जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप अचानक पीछे हट जाएंगे और कोई जवाब भी नहीं देंगे तो सवाल तो उठेंगे ही।'

'मुंह नहीं खोलोगे तो नाक दबाएंगे'

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज अध्यक्ष ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इंडस्ट्री में जवाबदेही जरूरी है और चुप रहकर विवाद खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, 'देखिए, मुंह नहीं खोलोगे तो नाक दबाएंगे, मुंह खुल जाएगा। हमने सीधे अप्रोच किया। प्रोड्यूसर बॉडी ने भी कॉन्टैक्ट किया। हमारे कहने पर रितेश सिधवानी और उनकी टीम ने तीन-तीन लेटर भेजे। बार-बार कहा गया कि बैठकर बात कर लीजिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आखिर में बोलते हैं कि 'हां ठीक है, मीटिंग करेंगे', मगर मीटिंग में आते ही नहीं। इंडस्ट्री पूरी हमारे दायरे में आती है, फिर कैसे नहीं आ सकते? बातचीत से हर चीज का हल निकल सकता है।'

'धुरंधर चली तो खुद को धुरंधर समझने लगे'

तिवारी ने रणवीर सिंह के स्टारडम और बदले रवैये पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब रणवीर का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उनकी फिल्में लगातार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, तब फरहान ने उन पर भरोसा जताते हुए 2023 में फिल्म के लिए साइन किया था।

तिवारी ने कहा, 'रणवीर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए इंडस्ट्री ने हमेशा सपोर्ट किया। मगर इस तरह काम करेगा तो नहीं चलेगा। आपकी फिल्म 'धुरंधर' चली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद धुरंधर हो गए। इंडस्ट्री रिश्तों और भरोसे पर चलती है। अभी अगर आप बिना कुछ बताए विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे होगा? जब रणवीर की फिल्में नहीं चल रही थीं, उस वक्त इस आदमी ने आपको साइन किया। 2023 में आप पर भरोसा किया गया। अब आपका पार्ट वन, पार्ट टू हिट हो गया तो आपके पास कहानियां आना शुरू हो गईं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने कमिटमेंट भूल जाएं।'

'एक्सेल बहुत जेंटलमैन कंपनी है'

हालांकि, पूरे विवाद के बीच तिवारी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, 'एक्सेल बहुत जेंटलमैन कंपनी है। बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है। आज तक उनके खिलाफ कोई बड़ा डिस्प्यूट हमारे पास नहीं आया। इसलिए जब उन्होंने शिकायत की तो हमें मामला गंभीरता से देखना पड़ा। हमारी तरफ से अभी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी गई है। हम सिर्फ चाहते हैं कि सामने बैठकर बात हो। अगर फिल्म नहीं करनी है तो साफ-साफ बता दें।'

रणवीर सिंह पर बैन लगा?

सोशल मीडिया पर चल रही 'बैन' की खबरों पर भी FWICE अध्यक्ष ने सफाई दी। उन्होंने कहा, 'हमने बैन नहीं किया है। नॉन-कोऑपरेशन दिया है। हमारे लोग उनके साथ काम नहीं करेंगे, मगर इसे बैन कहना गलत होगा।'

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने की मोदी से मुलाकात

नयी दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।अभिनेता से राजनेता बने विजय का इस महीने की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद केंद्र के साथ पहला औपचारिक संवाद था। नये प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बैठक हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं का फोटो साझा करते हुए मुलाकात की जानकारी दी। दोनों के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु का नया नेतृत्व, दोनों ही अपने राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से साधने में जुटे हैं। श्री विजय की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गयी है लेकिन समझा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री के साथ श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठायेंगे।

अमित शाह का दो दिवसीय गुजरात दौरा: हरामी नाला में सुरक्षा पर पैनी नजर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे है। जिसमें वे भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अत्यंत संवेदनशील हरामी नाला चौकी का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने वाले है। 28-29 मई को निर्धारित यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हरामी नाला विवादित सर क्रीक क्षेत्र के करीब कच्छ के रण में स्थित एक संवेदनशील खाड़ी क्षेत्र है।भुज के पास कच्छ जिले में स्थित क्षेत्र अपनी उथली, दलदली और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह खाड़ी प्रणाली निगरानी में चुनौतीपूर्ण है, जिससे यह अवैध घुसपैठ, तस्करी, संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही और संभावित आतंकी मार्गों के लिए अतिसंवेदनशील बनी हुई है। सीमा सुरक्षा बल ने इस क्षेत्र से कई बार पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया है।

कच्छ से 1180 करोड़ की कोकीन जब्त

कच्छ । गुजरात में कच्छ से करीब 1180 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की गई है। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए तीनों ही आरोपी विदेशी हैं। गुजरात डीजीपी डॉ. केएलएन राव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस मुंद्रा पोर्ट पर एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही थीं। इसी के तहत मंगलवार की सुबह भारतीय समुद्री सीमा से एक कंटेनर जहाज पकड़ा गया।जहाज ब्राजील, कई लैटिन अमेरिकी देशों, मेक्सिको, अमेरिका और कराची होते हुए गुजरात के तट तक पहुंचा था। जहाज में नाइजीरिया की नागरिकता वाले दो आरोपी सवार थे, जिनमें से एक समुद्र में कूदकर फरार हो गया। पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि खेप दिल्ली के द्वारका में रहने वाले दो लोगों तक पहुंचाई जाने वाली थी। इनकी पहचान क्लैविन चुकवुमा (तंजानिया का नागरिक) और ब्यारुहांगा जेम्स (युगांडा का नागरिक) के रूप में हुई है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ।

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मंच जैसा काम किया :योगेंद्र यादव

नई दिल्ली। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यादव ने आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत ने संवेदनशील मामले में संवैधानिक अदालत के बजाय एक उपभोक्ता मंच की तरह काम किया है। उन्होंने दावा किया कि अंतिम फैसला बहुत पहले ही तय हो चुका था। यादव ने कहा कि वे अंतिम फैसला सुनने के लिए अदालत नहीं गए, क्योंकि उनके विचार में सिर्फ लिखित दस्तावेज और बारीकियाँ ही बाकी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दिनों की सुनवाई के बावजूद, पीठ ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने के बजाय शिकायत निवारण और मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित किया। यादव के अनुसार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों में कथित खामियों को दूर किए बिना ही बिहार चुनाव कराने की अनुमति दे दी, तभी मामला प्रभावी रूप से तय हो गया था।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया संचालित करने की शक्ति को बरकरार रखा है।

तकनीकी खराबी के कारण सैन फ्रांसिस्को उड़ान दिल्ली लौटी

नई दिल्ली। नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही

एअर इंडिया की उड़ान एआई-173 को बुधवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। बोइंग विमान में सवार सभी 230 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षितद हैं। एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है और अब उसकी विस्तृत तकनीकी जांच होगी। जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के करीब तीन घंटे बाद, जब विमान चीन के हवाई क्षेत्र में पहुंच चुका था, तभी एक तकनीकी समस्या का पता चला। एहतियात के तौर पर, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता द देकर विमान को तत्काल वापस दिल्ली मोड़ने का फैसला हुआ। आंकड़ों के मुताबिक, विमान लगभग साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक हवा में रहा, जिससे लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल बन गया।एअर इंडिया ने बताया कि एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सहायता और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस साल की शुरुआत में 29 जनवरी को लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को अपना फैसला सुनाया।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया सांविधानिक है। पीठ ने कहा, चुनाव आयोग ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और न ही एसआईआर के दौरान नियमों के खिलाफ जाकर मतदाताओं के नाम काटे गए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 , प्रतिनिधि कानून, 1950 के तहत एसआईआर कराने की शक्ति दी गई है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अपनी वैधानिक शक्तियों के परे जाकर काम किया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि एसआईआर लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करती है।

अदालत ने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग के पास शक्ति है कि वे मतदाता सूची के उद्देश्य के लिए नागरिकता की भी जांच कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता कि कौन भारतीय नागरिक है या नहीं, लेकिन मतदाता सूची के संबंध में नागरिकता संबंधी सवालों की जांच करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने कहा प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत चुनाव आयोग के पास इसका वैधानिक अधिकार है।

अदालत ने ये भी साफ किया कि अगर आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो आयोग उस व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है। मतदाता सूची से

कोई भी नाम हटाना सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए फैसले पर निर्भर होगा।

एसआईआर के खिलाफ अधिकांश याचिकाएं पिछले साल जून में दाखिल की गई थीं, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान शुरू करने का फैसला लिया था। इसके बाद यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दी गई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाए रखने तथा फर्जी या अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए यह अभियान जरूरी है।

याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर अभियान की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं दायर करने वालों में लोकतांत्रिक सुधार संघ, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले आदि बड़े नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिले अधिकारों के तहत नहीं आती है। विवाद का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग की वह शर्त है, जिसके तहत जिन मतदाताओं का नाम 2002 या कुछ राज्यों में 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध साबित करना होगा, जिसका नाम उन सूचियों में दर्ज था।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह शर्त गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती है, क्योंकि उनके पास पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा दस्तावेजी प्रमाण मिलना मुश्किल है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावित मतदाताओं को राहत देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अंतरिम निर्देश भी जारी किए थे। शुरुआत में चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज तय किए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा बोली- विपक्ष का चेहरा बेनकाब

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके आरोपों की पोल खोल दी है। यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वैध और संवैधानिक करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदाता सूची का यह विशेष पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक आवश्यकता को मजबूत करता है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को इस तरह की प्रक्रिया चलाने का अधिकार है।

फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ढक्र प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक घोषित कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस अवैध मतदाताओं के साथ खड़ी थी। भाजपा ने दावा किया कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक दायरे में है और कांग्रेस दुष्प्रचार फैला रही है।

असम विधानसभा में विपक्ष का भाजपा पर बड़ा हमला

यूसीसी बिल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है

गुवाहाटी। असम विधानसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर लाए गए विधेयक को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया और प्रस्तावित कानून को पारित करने से पहले सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श की मांग की। 'द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 विधेयक' पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने यह भी कहा कि यह समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता वाजेद अली चौधरी ने कहा, ''समान नागरिक संहिता में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, वे पहले से ही अलग-अलग कानूनों के माध्यम से लागू हैं। बाल विवाह, बहुविवाह, विवाह और तलाक का पंजीकरण, गुजारा भत्ता और अन्य मुद्दे विभिन्न कानूनों द्वारा शासित हैं।

फिर यूसीसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानूनों का सरलीकरण नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाना है। चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा, भाजपा इसे केवल राजनीति के लिए लायी है। लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक नहीं है। और जो कानून आदिवासियों को बाहर रखता है, उसे समान कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी लाना बेरोजगारी, बाढ़ और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक रणनीति है।

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और 'लिव-इन रिलेशनशिप' जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से, असम सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता से संबंधित एक विधेयक पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, विधेयक में कहा गया है कि यह असम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा।

इसमें कई दंडात्मक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें बहुविवाह या दो विवाह के लिए सात साल की कैद और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न

कराने पर तीन महीने की जेल शामिल है। चौधरी का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा कि 2018 में तत्कालीन विधि आयोग ने यूसीसी की आवश्यकता नहीं होने की राय दी थी। आयोग के अनुसार, यदि सरकार इसे लागू करना भी चाहती है तो उसे सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श करना चाहिए। उन्होंने कहा, असम सरकार ने विभिन्न धार्मिक संगठनों से चर्चा किए बिना यह विधेयक पेश कर दिया है। कई धर्म और सामाजिक समूह विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं रखते।

हमारी पहचान 'विविधता में एकता' है। सिकदर ने मांग की कि विधानसभा में इस विधेयक को पारित करने से पहले व्यापक परामर्श किया जाए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मसौदा कानून को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी की एक बूथ बैठक में कहा था कि एक घर के दो सदस्यों के लिए दो कानून नहीं हो सकते और एक घर के लिए एक ही कानून होना चाहिए।

इसलिए यूसीसी का शीर्षक बदलना चाहिए क्योंकि यह राज्य के सभी लोगों को शामिल नहीं करता। सिकदर ने सवाल उठाया कि सरकार कुछ लोगों को इसमें शामिल न करके उनके साथ अन्याय क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, यह विधेयक केवल भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि इन विषयों से जुड़े पहले से ही मौजूदा कानून मौजूद हैं। हमें यूसीसी की आवश्यकता नहीं है।

खेल

प्रमुख समाचार

फ्रेंच ओपन में 17 वर्षीय मोयसे कुआमे ने रचा इतिहास

धर्मशाला। मोयसे कुआमे ने फ्रेंच ओपन में

अपने ग्रैंड स्लैम डेब्यू को यादगार बना दिया। 17 वर्षीय फ्रांसीसी खिलाड़ी ने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन मारीन सिलिच को 7-6 (4), 6-2, 6-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। रोलां गैरों में घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच कुआमे ने बेहद परिपक्व खेल दिखाया। विश्व रैंकिंग में 318वें स्थान पर मौजूद यह खिलाड़ी 2008 या उसके बाद जन्मे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम मुकाबले में जीत दर्ज की है।

वह 1991 के बाद रोलां गैरों में मैच जीतने वाले सबसे युवा फ्रांसीसी खिलाड़ी भी बने। मैच के बाद कुआमे ने कहा, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। हमने टीम के साथ रणनीति पर बहुत काम किया था। यहां के माहौल और दर्शकों को मैं पहले से थोड़ा जानता था, इसलिए आत्मविश्वास बना रहा। मौजूदा चैंपियन कोको गॉफ ने हमवतन टेलर टाउनसेंड को 6-4, 6-0 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। हालांकि मैच की शुरुआत गॉफ के लिए आसान नहीं रही और टाउनसेंड ने शुरुआती गेम में उनकी सर्विस तोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद गॉफ ने शानदार वापसी की और मैच के आखिरी 12 में से 11 गेम जीत लिए। दूसरे सेट में टाउनसेंड एक भी गेम नहीं जीत सकीं। गॉफ ने लगातार सातवीं बार फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई है। विश्व नंबर-1 अरीना सबालेंका ने स्पेन की जेसिका बौजास मानेइरो को 6-4, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। गर्म मौसम और तेज क्ले कोर्ट पर सबालेंका ने नेट के पास आक्रामक खेल दिखाया। मैच के बाद उन्होंने कहा, इस समय खेल का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि मैं नेट पर आकर अंक जीत पा रही हूं। मैंने अपने खेल के इस हिस्से में काफी सुधार किया है और इस पर गर्व है। वहीं नाओमी ओसाका ने जर्मनी की लौरा सीगमंड को 6-3, 7-6(3) से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 142 अंक गिरा निफ्टी 23,907 पर हुआ बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली, जहां बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में कमजोरी ने प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बनाया। कारोबारियों ने वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच सतर्क रुख अपनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी50 मामूली गिरावट के साथ 6.55 अंक टूटकर 23,907.15 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 141.90 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,867.80 के स्तर पर बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स में उतार-चढ़ाव के बावजूद मिडकैप शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स ने न केवल बाजार की चाल को दोहराया, बल्कि दिन के कारोबार में नया ऑल-टाइम हाई भी छू लिया। यह लगातार बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा है।

1 जून से डोमेस्टिक फ्लाइट की उड़ानें होंगीं कम

नईदिल्ली। अगर आप जून, जुलाई या अगस्त के महीनों में देश के भीतर कहीं हवाई सफर (डोमेस्टिक ट्रेवल) करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपकी जेब का बजट बिगाड़ सकती है। भारत के घरेलू विमानन बाजार पर एकछत्र राज करने वाली दो सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां एयर इंडिया और इंडिगो, आगामी 1 जून 2026 से अगले तीन महीनों के लिए अपनी उड़ानों की संख्या में बड़ी कटौती करने जा रही हैं। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया जहां अपनी उड़ानों में 15% तक की कमी करेगी वहीं इंडिगो भी अपनी क्षमता में 5% से 7% तक की कटौती करने की तैयारी में है। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इस युद्ध जैसी स्थिति के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं जिससे कंपनियों की लागत बहुत बढ़ गई है।

महंगाई का डबल अटैक दालों में तेजी के संकेत

नईदिल्ली। देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर सीधे आम आदमी की रसोई पर दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में चना और अरहर दाल के दाम और बढ़ सकते हैं। वहीं डीजल-पेट्रोल की महंगाई और माल ढुलाई खर्च बढ़ने से खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक महंगे होने की आशंका है। अल-नीनो के कारण कमजोर मानसून की चिंता ने भी बाजार का तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में आम लोगों का घरेलू बजट और बिगड़ सकता है। इंडिया पल्सेज एंड ग्रेंस एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चना और अरहर की आवक कम हो रही है। वहीं विदेशों से आयात भी घटा है। इसी वजह से बाजार में इन दालों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बीते वित्त वर्ष में कुल दाल आयात घटकर 57.76 लाख टन रह गया, जबकि इससे पहले यह 69.3 लाख टन था।

जापान ने भारतीय आमों के आयात पर लगाई रोक

नईदिल्ली। जापान ने इस सीजन में भारत से ताजे आमों के आयात पर रोक लगा दी है। जापानी अधिकारियों ने भारतीय ट्रीटमेंट और पैकिंग केंद्रों में फ्यूमिगेशन तथा डिसइन्फेक्शन प्रक्रिया में कमियां पाए जाने के बाद यह फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में जापान के प्लांट क्वारंटीन अधिकारियों ने भारत के कुछ ट्रीटमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्यात से पहले आमों को कीट-मुक्त बनाने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया जापानी मानकों के अनुरूप नहीं थी। इसके बाद जापान के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि 25 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए भारतीय निरीक्षण प्रमाणपत्रों वाले आम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक भारत अपनी प्रक्रियाओं में सुधार साबित नहीं कर देता।

पेट्रोल के बढ़ते भाव : महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और नीति-निर्माण की चुनौती

डॉ. प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ समय से देश के शहरों और गांवों में एक चिंता लगातार सुनाई दे रही है—पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें। यह चिंता केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हर उस नागरिक पर पड़ता है जो रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर केवल पेट्रोल पंप तक नहीं रहता; वह परिवहन, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री, कृषि लागत और घरेलू बजट तक पहुंच जाता है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को केवल एक आर्थिक घटना मानना पर्याप्त नहीं है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत प्रश्न भी है, जो सरकार, बाजार और नागरिक—तीनों से जुड़ा हुआ है।

भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार नहीं है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और विकास की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। देश का विशाल परिवहन तंत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यही कारण है कि पेट्रोल के बढ़ते भाव हमेशा जनचर्चा और राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक विदेशों से खरीदता है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल

की कीमत बढ़ती है तो भारत को अधिक भुगतान करना पड़ता है, और उसका असर अंततः खुदरा कीमतों में दिखाई देता है।

वैश्विक तेल बाजार केवल आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसके पीछे भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, प्रमुख तेल उत्पादक देशों की उत्पादन नीतियां, रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे कारक तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष या आपूर्ति संकट का असर कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर दिखाई देने लगता है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि घरेलू बाजार को इन परिस्थितियों से पूरी तरह अलग नहीं रखा जा सकता। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों का पूरा सच केवल वहीं तक सीमित नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में करों की भी बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोल की अंतिम कीमत में कच्चे तेल की लागत के अलावा केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क, राज्य सरकारों का मूल्य वर्धित कर (वैट), परिवहन लागत और डीलर कमीशन भी शामिल होता है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। तेल पर लगने वाले कर सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण में किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर यही कर आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डालते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और कर संरचना में कोई राहत नहीं मिलती, तब उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। यही स्थिति अक्सर राजनीतिक बहस का कारण बनती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर दिखाई देता है। टैक्सी चालक, ऑटो चालक, ट्रक मालिक, बस संचालक और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लाखों लोग बढ़ती लागत का सामना करते हैं। उनके सामने सामान्यतः दो विकल्प होते हैं—या तो बढ़ी हुई लागत को स्वयं वहन करें अथवा किराए और सेवा शुल्क बढ़ाकर उसका भार उपभोक्ताओं पर डाल दें। अधिकांश मामलों में दूसरा विकल्प अपनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं।

विकास योजनाओं पर बड़ी मुहर

एमआईसी बैठक में 18 एजेंडों पर हुई चर्चा

रायपुर। आज राजधानी में रायपुर नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर विकास, पेयजल व्यवस्था, निर्माण कार्यों और जनसुविधाओं से जुड़े कुल 18 एजेंडों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर मीनल चौबे ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि जर्जर हो चुकी पुरानी नगर निगम बिल्डिंग के पुनर्विकास को लेकर निगम गंभीरता से काम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कमर्शियल मॉडल पर परियोजना विकसित करने की तैयारी की जा रही है। शहर में लगातार गहराते पेयजल संकट पर चर्चा को लेकर भी मीनल चौबे ने जानकारी साझा की।

महापौर ने मीनल चौबे कहा कि पुरानी निगम भवन की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, इसलिए उस स्थल के बेहतर उपयोग और पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और आम जनता से चर्चा के बाद अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा।

पेयजल संकट को लेकर मेयर ने कही ये बात

शहर में लगातार गहराते पेयजल संकट को लेकर भी एमआईसी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि पानी की समस्या केवल दो-चार दिनों की नहीं है, बल्कि भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। नगर निगम इस मुद्दे पर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है और व्यवहारिक प्रस्तावों को एमआईसी की स्वीकृति के बाद लागू किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि शहर का बड़ा हिस्सा अब भी पेयजल के लिए भूजल पर निर्भर है, इसलिए समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम लगातार जल संकट को लेकर बैठकें कर रहा है और हर स्तर पर समाधान तलाशने का प्रयास जारी है।

उन्होंने बताया कि नवीन मार्केट क्षेत्र के विकास को लेकर भी निगम काम करेगा। हालांकि पुरानी निगम बिल्डिंग में निर्माण को लेकर ज्यादा तकनीकी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन नवीन मार्केट क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं, जिन पर विचार-विमर्श कर आगे निर्णय लिया जाएगा। बैठक में प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों के लिए संकल्प सोसायटी के माध्यम से करीब 10 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा खेल एवं कल्याण विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी राशि मंजूर की गई।

आमानाका क्षेत्र में प्रस्तावित गार्बेज डिपो परियोजना को लेकर भी एमआईसी की बैठक में चर्चा हुई। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि इस संबंध में पहले से एमओयू किया जा चुका है, जिसकी अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक है। अब इस विषय को एमआईसी में लाया गया है और नियमानुसार नगर निगम आगे अनुमति प्रदान करेगा। बैठक में महादेव घाट के जीर्णोद्धार प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं शहीद आकाश राव गिरपुंजे के परिवार से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। महापौर ने कहा कि शहीदों से बढ़कर कुछ नहीं होता और निगम परिवार की भावनाओं का पूरा सम्मान करेगा। उन्होंने बताया कि शहीद आकाश राव गिरपुंजे की प्रतिमा लाखे नगर चौक में स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

जिपं को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्साः साय

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व राशि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि का हिस्सा दिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा की थी, जिसका अब राज्य शासन द्वारा पालन कर दिया गया है।

खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पूर्ववत दिया जाएगा, जबकि शेष 67 प्रतिशत राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच निर्धारित स्लैब के अनुसार किया जाएगा।

जारी आदेश के तहत 7.50 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह ग्राम पंचायत को मिलेगी। 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत और 10 प्रतिशत जिला पंचायत को दिया जाएगा। 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि में ग्राम पंचायत को 70 प्रतिशत तथा जनपद और जिला पंचायत को 15-15 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इसी तरह 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की राशि में ग्राम पंचायत को 60 प्रतिशत और जनपद व जिला पंचायत को 20-20 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। 50 लाख रुपये से अधिक की राशि में ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत तथा जनपद और जिला पंचायत को 25-25 प्रतिशत राशि मिलेगी।

राज्य शासन ने निधि के उपयोग के दायरे का भी विस्तार किया है। अब इस राशि का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम निर्माण, पहुंच मार्ग तथा वाचनालय निर्माण जैसे कार्यों में किया जा सकेगा। जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा जहां खनन गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राजधानी के थाना कोतवाली में 'ई-मालखाना' प्रणाली शुरू

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में जप्त माल के प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ई-मालखाना प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था का शुभारंभ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले द्वारा किया गया। इस पहल को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार ई-मालखाना प्रणाली को थाना कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह गहरवार और मालखाना मुहर्रिर प्रेमसागर नेताम के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य थाना में जप्त किए गए सामान का सुरक्षित संधारण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और आवश्यकतानुसार त्वरित खोज एवं निगरानी सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को ई-मालखाना प्रणाली की विस्तृत कार्यप्रणाली का डेमो प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि अब जप्त सामग्री का डिजिटल पंजीयन किया जाएगा और प्रत्येक वस्तु को बारकोड आधारित पहचान दी जाएगी। साथ ही मालखाने में सामग्री को रैकवाइज वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। प्रणाली के तहत मालखाने को،1,،2, क्क्1, क्क्2 जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सामान को वर्गीकृत किया गया है, ताकि किसी भी जप्त वस्तु की लोकेशन तुरंत पता लगाई जा सके। इस प्रक्रिया से रिकॉर्ड प्रबंधन और सामग्री की निगरानी पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी।इस अवसर पर डीसीपी सेंट्रल ज़ोन उमेश प्रसाद गुप्ता, डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर, एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री साव ने 12.29 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर । प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने नारायणपुर प्रवास के दौरान जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने एजी सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 12 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका नारायणपुर के विकास के लिए 5 करोड़ रूपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार नारायणपुर जिले को विकसित, खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं ने शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है।

एनआईटी रायपुर ने स्मृति पुस्तकालय के तहत दान की 30 कंप्यूटर सिस्टम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण बनती जा रही है। इस पहल के माध्यम से लोग स्वेच्छा से पुस्तकें और इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट दान कर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में आज एनआईटी रायपुर ने 30 कंप्यूटर सिस्टम जिला प्रशासन को दान कीं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उनके इस सराहनीय योगदान की सराहना करते हुए एनआईटी के प्रतिनिधि एसोसिएट प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा को प्रमाण पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास से जरूरतमंद एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। उल्लेखनीय है कि स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत अब तक 13 हजार 500 से अधिक पुस्तकें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दान किए जा चुके हैं।

इन संसाधनों का लाभ लेकर अनेक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई दिशा दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे भी इस पुनीत पहल से जुड़कर ज्ञान के दान में भागीदार बनें और युवाओं के सपनों को साकार करने में सहयोग दें। पुस्तक अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करने के इच्छुक नागरिक 94060 49000 एवं 94255 02970 से संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

थम ही नहीं रहा अपराध का सिलसिलाः दीपक बैज

रायपुर। पूरे प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पेंड्रा के कोटमी बाजार में सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई,पिछले 24 घंटों के भीतर ही राजधानी रायपुर के कुशालपुर क्षेत्र में गैंगवार हुआ, राजधानी रायपुर के ही गंज थाना क्षेत्र में सरेआम चाकूबाजी हुई, एक युवक हत्या हो गई, उनसे जेवरात लूट लिए गए, बिन्द्रानवागढ़ के देवभोग में महिला समेत परिवार के चार सदस्यों पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया, महिला की गर्दन पकड़ कर ब्लेड चला दिया गया जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, मौके पर मौजूद उनके दोनों बेटे और पति गंभीर रूप से घायल हैं,जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ खत्म होने लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग राजनैतिक विद्वेष की पूरा करने, विपक्षी दल के नेताओं को प्रताड़ित करने में कर रही है, अपराध रोकना इस सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। भाजपा षडयंत्र रचती है, पुलिस और प्रशासन उसपर अमल करके दमन करती है। इस सरकार में पीड़ित ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं।

दुर्भावनापूर्वक जनगणना के आंकड़े बदलवा रही हैः शुक्ला

रायपुर। सरकार दुर्भावनापूर्वक जनगणना के वास्तविक आंकड़े बदलवा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के द्वारा एकत्रित किए गए वास्तविक तथ्यों में फेरबदल करवाने के लिए दबाव डाल रही है। किसी घर मे यदि उज्जवला गैस का कनेक्शन है लेकिन गैस नहीं भरवा पाने के कारण उनके यहां खाना चूल्हे पर बन रहा है, किसी ने अपने यहां शौचालय नहीं होने की बात लिखवाया है, कोई झोपड़ी में रहता है तथा वह सर्वे सूची में पात्र है उसे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है तो उसने वही लिखवाया है तो इन आंकड़ों को जनगणना कार्य में लगे उच्चाधिकारी बदलवा रहे है। यह सरकार की छवि सुधारने की कोशिश में किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनगणना के वास्तविक आंकड़े तथा तथ्यों को बदलना देशद्रोह का काम है, देश के हजारों-करोड़ों रू. खर्च करके जनगणना कार्य करवाया जा रहा है। जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े आयेंगे उसी के आधार पर आने वाले दशक के लिए देश की तमाम योजनायें बनाई जायेगी। विकास कार्यों की रूपरेखा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में योजनायें बनेगी। गरीबों वंचितों के कल्याण की योजना बनेगी।

ट्रेड लायसेंस नही, रोजगार शुरू नही कर पा रहे लोगः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने गुमास्ता लाइसेंस को बंद कर व्यापार व्यवसाय के लिए ट्रेड लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया लेकिन ट्रेड लायसेंस देने की व्यवस्था दुरुस्त नही किया जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है।चिप्स की लापरवाही के चलते 50 हजार से अधिक लोगो को स्वंय का रोजगार शुरू करने ट्रेड लाइसेंस नही मिला।हजारों लोगों का लाइसेंस नवीनीकरण नही हुआ है।कांग्रेस सरकार में लाइफ टाइम गुमास्ता व्यवसाय शुरू करने दिया जाता था।निकाय पर इसकी जिम्मेदारी थी।आसानी से गुमास्ता बन जाता था।भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी की नीति ने गुमास्ता को बंद कर नया नियम बना दिया।अब ट्रेड लाइसेंस के लिए प्रति फिट फीस ली जा रही है।अलग अलग निकायों में फीस अलग अलग है।फेरीवाला, खोमचा वाला चलित वाहन में व्यवसाय करने वालो को भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है ।लेकिन ट्रेड लाइसेंस बनाने की सिस्टम आज भी अपडेट नही है। सरकार के पास जब ट्रेड लाइसेंस देने की पूरी तैयारी नही थी तो गुमास्ता देने की प्रक्रिया को बंद क्यो किया गयासरकारी तंत्रों की नाकामी आखरी व्यापारी क्यों भुगतेकांग्रेस मांग करती है।

रामभद्राचार्य सनातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं : तिवारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के लगातार आ रहे राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश में संतो और गुरुओं का स्थान हमेशा से राजनीति से ऊपर और सर्वमान्य रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश जगद्गुरु रामभद्राचार्य अपने बयानों और रुख से संत परंपरा की गरिमा को गिराकर खुद को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में स्थापित कर चुके हैं। उनके बयान पूरी तरह से भाजपा के वैचारिक और चुनावी एजेंडे को लाभ पहुंचाने के लिए प्रायोजित प्रतीत होते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि, रामभद्राचार्य के बयानों को सिलसिलेवार ढंग से रेखांकित करते हुए भाजपा और उनके अंतर्संबंधों पर कई गंभीर सवाल उठाए है। रामभद्राचार्य जी का चुनावी एजेंट की तरह भविष्यवाणियां करना कथा के पवित्र मंचों से आएंगे तो मोदी ही जैसे नारे लगाना और भाजपा के लिए 350 से अधिक सीटें आने का दावा करना किसी संत का कार्य नहीं, बल्कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की भाषा है।

11 जून से आमरण अनशन करेंगे उत्तम जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डी.एड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा अब और गंभीर रूप लेता जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा है कि यदि 10 जून तक पात्र डी.एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो वे 11 जून से आमरण अनशन शुरू करेंगे। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में डी.एड. महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लगभग 2300 सहायक शिक्षक पद रिक्त हैं। इनमें से करीब 1600 पद आदिवासी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से जुड़े बताए गए हैं। अभ्यर्थी पिछले 153 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से नियुक्ति नहीं मिलने के कारण वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। उत्तम जायसवाल ने अपने पत्र में दावा किया है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक डी.एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी है।

एनएच-49 पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस

एनएचएआई ने प्रदेश में 1033 की सुविधाओं में किया विस्तार

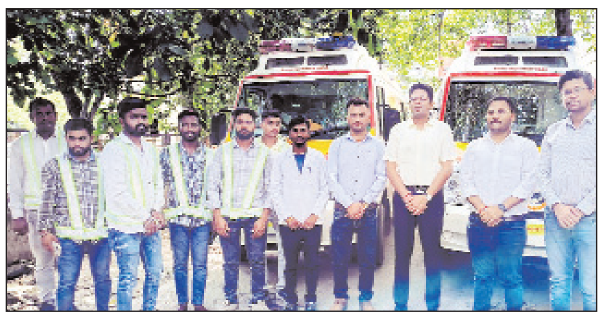

रायपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर द्वारा अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग- 49 पर बिलासपुर से रायगढ़ के बीच सफर करने वाले यात्रियों की आपातकालीन सहायता के लिए पाराघाट टोल प्लाजा और केसला टोल प्लाजा पर तैनात किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर के परियोजना निदेशक श्री मुकेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले प्रत्येक यात्री की जान और उनकी सुरक्षा एनएचएआई की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर किसी भी आपात स्थिति में राहगीरों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अगली बार जब आप राजमार्गों पर किसी लंबे सफर पर निकलें, तो अपनी गाड़ी की तकनीकी जांच करने के साथ-साथ अपने मोबाइल की स्पीड डायल लिस्ट में 1033 नंबर को जरूर सेव कर लें। क्योंकि जब हाइवे पर मुश्किलें रास्ता रोकती हैं, तो यही चार अंक संजीवनी बनकर आपकी मदद करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों में सफ़र का साथी डायल 1033: टोल-फ्री डायल 1033 हाइवे पर 24×7 आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। हाईवे पर अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या इंजन फेल हो जाए। अगर हाइवे पर कोई पेड़ गिर गया हो, मवेशी आ गए हों या कोई भारी मलबा पड़ा हो। यात्रा के दौरान अगर अचानक किसी सह-यात्री की तबीयत बिगड़ जाए। टोल प्लाजा या फास्टैग संबंधी कोई समस्या हो या हाइवे पर असुरक्षा महसूस हो रही हो, तो 1033 डायल करें।

कैसे काम करता है डायल 1033: जैसे ही कोई राहगीर 1033 नंबर पर फोन करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का कॉल सेंटर तुरंत हरकत में आ जाता है। फोन करने वाले व्यक्ति से हादसे की सही जगह (लोकेशन) पूछी जाती है और कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस या पेट्रोलिंग गाड़ी मदद के लिए मौके पर पहुँच जाती है। इसके जरिए राहगीर को तुरंत हर जरूरी मदद दी जाती है। अगर कोई घायल हो, तो उसे बिना देर किए पास के अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया जाता है। वहीं, अगर कोई दूसरी समस्या हो, तो क्रेन या पेट्रोलिंग गाड़ियों की मदद से उसे तुरंत दूर किया जाता है।

बारनवापारा के देवपुर जंगल में दिखी दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बारनवापारा क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत देवपुर जंगल में आयोजित देवपुर समर कैंप 2026 के दौरान दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी (जायंट मालाबार स्क्रिरल) दिखाई दी। इस दुर्लभ वन्यजीव के दिखने से वन विभाग, प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों में उत्साह है।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास विकसित हो रहे हैं।बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा 16 मई से 22 मई 2026 तक देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप के पहले दिन 16 मई को आयोजित बर्डिंग ट्रेल के दौरान इस दुर्लभ गिलहरी को देखा गया। इसकी पहचान प्रकृति प्रेमी एवं साइबर रिस्क एक्सपर्ट श्री हेमंत वर्मा ने की।

विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटूफा इंडिका है, भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। इसकी पूंछ सहित लंबाई लगभग तीन फीट तक होती है। इसके शरीर पर गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का सुंदर मिश्रण होता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती है।

यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-2 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार या व्यापार करना कानूनन अपराध है। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.